असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 मार्च, 2023

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 03 मार्च, 2023 ई0

अष्टम सत्र — 12 फाल्गुन,1944(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : एक मिनट-एक मिनट ।

माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज प्रथम पाली की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी । समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बैठक में भाग लेने की कृपा करें ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण किया जाय ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, बहुत गंभीर विषय है । डी0जी0पी0...

अध्यक्ष : आपके गंभीर विषय को आपके ही सदस्य लोग नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, तमिलनाडु के डी0जी0पी0 का बयान असत्य है । तमिलनाडु के त्रिपुर, कोयम्बटूर एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय लोगों के द्वारा बिहारी मजदूरों को घातक हथियार से बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है और मजदूर भागकर वापस जमुई, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आ गये हैं । जिस दिन हत्या हो रही थी महोदय, कल रात में 7-8 बजे लखीसराय का एक लड़का चन्दन कुमार मोबाईल पर फोन किया कि सर, हमलोग घर के अन्दर कैद हैं, फैक्ट्री के अन्दर कह रहा है कि आप सब लोग जल्दी से निकलिए, सो बचा लीजिए । माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी वहां गये थे और वहां पर हत्याओं का दौर चल रहा है । सरकार एक विशेष टीम वहां भेजे और वहां से सभी लोगों को सुरक्षित लाने का प्रयास करे । वहां 12 से अधिक लोगों की हत्या हो गई है, अगर महोदय, डी0जी0पी0 का इस तरह का बयान आयेगा, एक सर्वदलीय कमिटी बनाकर वहां पर भेजे सरकार .....

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, इसपर सरकार का उत्तर होना चाहिए । माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वहां गये हैं, एक बार इसपर उप मुख्यमंत्री जी का बयान आना चाहिए ।

टर्न–1/आजाद/03.03.2023

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री । माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष जैसा कि कह रहे थे गंभीर मुद्दे की बात कर रहे हैं । यह मुद्दा कल से ही दोनों सदन में आ रहा है और सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए यहां के डी0जी0पी0 को निर्देश देकर वहां के डी0जी0पी0 से रिपोर्ट मांगी है । वहां से रिपोर्ट में बात आयी है कि यह घटना जिस तरह की है, वैसी प्रमाणित नहीं हो रही है । लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं तो इसमें हम सरकार की तरफ से दो ही निवेदन करेंगे कि अगर वह घटना सही है, उसका कोई स्पष्ट प्रमाण हो तो दें, निश्चित रूप से बिहार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी पहली बात, दूसरी बात इनके लखीसराय के या बिहार के ....

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें, सरकार जवाब दे रही है, कृपया सुनें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इन्होंने बताया कि लखीसराय का कोई आदमी इनसे सम्पर्क किया है तो इसी क्रम में हम सदन के सारे माननीय सदस्यों को कहते हैं कि किन्हीं के सम्पर्क में कोई ऐसा आदमी है जो कहीं फंसा हुआ है तो उसका नाम, पता, वहां चेन्नई या तमिलनाडु के किसी इलाके में, वहां का पूरा पता के साथ दें, सरकार उस आदमी को खोजकर उसको वापस लाने की व्यवस्था सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य तारकिशोर प्रसाद ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने....

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रश्नकाल को तो चलने दीजिए । प्रश्नकाल को चलने दीजिए । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल से .....

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें । सुदय जी, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दिया जाय । पूरा विडियो चल रहा है । कल हमसे डायरेक्ट बात किया है और इसके लिए एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जॉच करावें । इतना संवेदनहीनता उचित नहीं है सरकार की ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप उसको सरकार को दे दें । माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष कल से ही व्याकुल हैं इस इशु को लेकर के .....

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें, आप सुनें माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : आपलोग सुन तो लीजिए ।

अध्यक्ष : आपलोग स्थान तो ग्रहण कीजिए । आप ही सुनाईयेगा, सरकार का नहीं सुनियेगा ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अनपार्लियामेंट्री है क्या ? आप मेरा नाम क्यों ले रहे थे, जब सुनना ही नहीं है तो । आप बोल रहे थे न कि हम बोलें । सुन तो लीजिए, बैठाये अपने लोगों को ।

अध्यक्ष : सुनने के लिए न कह रहे हैं । वे कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनिए । माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल का हमने दृश्य भी देखा विधान सभा में । जो दो वीडियो के बारे में जिक्र किया जा रहा है, दो विडियो जो चलाया गया है, कल इन लोगों ने हंगामा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लेते हुए अपने अधिकारियों को वहां के अधिकारियों से इस मामले की सत्यता को देखते हुए, सत्य जानने के लिए अधिकारियों ने सम्पर्क किया और वहां के तमिलनाडु के जो डी0जी0पी0 हैं, पहले हम उनका ब्यान जो है, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेजी में विडियो रिलिज किया था, उसका अनुवाद हम करवाकर के लाये हैं हिन्दी में, पहले एक बार ब्यान सुन लीजिए ।

श्री शैलेन्द्र बाबू, डी0जी0पी0, तमिलनाडु का ब्यान- मैं शैलेन्द्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल, तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूँ । बिहार में किसी ने यह कहते हुए एक झूठा और शरारती विडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है । दो विडियो पोस्ट किये गये हैं, उस विडियो का हो सकता है आप जिक्र कर रहे हों । दोनों विडियो झूठे हैं, ये दोनों घटनायें काफी पहले त्रिपुर और कोयम्बटूर जिलों में हुई थी और दोनों ही मामले में वे तमिलनाडु के लोगों और प्रवासी श्रमिकों के बीच संघर्ष नहीं है । एक विडियो जहां बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा जो विडियो है कोयम्बटूर का, वो स्थानीय निवासी केवल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं । यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिक बिहारियों पर हमला किया गया है । महोदय, यह डी0जी0पी0 का ब्यान है और जाहिर सी बात है कि इस गंभीरता को देखते हुए ही यह विडियो रिलीज किया है और सत्यता बतायी गयी है । लेकिन अलग से अगर कोई इनफॉरमेशन है तो दीजियेगा लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि

हमने कई बार बाहर में भी पहले भी कहा है कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है और नकारात्मक .....

(व्यवधान)

सुन लीजिए न, आप बोलियेगा न, आप बैठिए न । केवल नकारात्मक राजनीति करना । बोलेंगे भारत माता की जय और जरा इनसे पूछिए कि तमिलनाडु भारत का अंग नहीं है क्या, तमिलनाडु भारत का अंग है न ? जब आप भारत माता की जय कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं । यह कोन सा देश भक्ति है पहली बात, अगर कोई ऐसी घटना होगी तो न यहां की सरकार और न वहां की सरकार इसको टौलरेट करेगी । अगर ऐसी कोई बात हुई भी होगी तो सरकार जो है, उन दोषियों को बख्सने का काम बिल्कुल नहीं करेगी .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : समझने की कोशिश कीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : आप बैठिए न । अध्यक्ष महादेय, कल तो .....

अध्यक्ष : अरूण शंकर जी, आप स्थान ग्रहण करें । माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जवाब हो रहा है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इतना जरूर कहेंगे, इससे पहले एक और मामला उठाया था, जो शहीद हो गये थे, उनके पिता को एरैस्ट कर लिया गया । जरा पूछिए कि वह दलित परिवार, जब वह जवान शहीद भी नहीं हुआ था, उससे पहले से विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था ? एक मिनट, आप लोग बात बिना जानकारी के अभाव में कहते हैं । बिना सत्यता का भेरीफाई किये हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस राज्य का और विधान सभा में कुछ भी बोल देना और टेबुल उठा-उठा कर पटकना, मतलब आप हड़बड़ाईए नहीं, आप निश्चिंत रहिए, बैठिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए । बैठिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लिए, अब उप मुख्यमंत्री जी, आसन से इजाजत लेकर वे अपनी बात को रख रहे हैं । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

टर्न-2/शंभु/03.03.23

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : ये लोग कल प्रेस कांफ्रेंस किये और प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और परिषद् ने नेता विरोधी दल लेकिन इनको भुला दिया गया, अब इनलोगों में क्या तकरार है हमको तो नहीं पता, लेकिन नेता विरोधी दल को यही कहेंगे कि बहुत लोग आपकी पार्टी में ऐसे हैं जो आपको नापसंद करते हैं

तो थोड़ा उसपर अध्ययन करने की जरूरत है और तब्दीली करने की जरूरत है । महोदय, दूसरी बात कि हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि भैय्या आजकल बिना सत्यता के, बिना प्रमाण लिये हुए, बिना पड़ताल किये हुए, बिना वेरीफाई किए हुए कुछ बी0जे0पी0 माइंडसेट की जो मीडिया है वह भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है । महोदय, न्यूज का काम है, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाय सच्ची खबर को दिखाया जाय और आजकल बिना भेरीफाई किये हुए कोई भी कुछ भी चला देता है जिससे तनाव का वातावरण रहता है । इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए । आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य । माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, चिल्लाने से थोड़े कोई फायदा होनेवाला है ?

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रेस्पोंसिबल पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं और जो आप लेकर हाथ में बैठे हैं पहले उसकी भी जॉच करा लीजिए, चूंकि इसके पहले दो खबरें जो गंभीरता का सवाल लेकर आप हाऊस में आये वे नकली निकले और फर्जी निकले । इसलिए आगे अगर कोई बात कहिये तो इस चीज को देख लीजिए । सुन लीजिए, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, जो वीडियो दिखाइयेगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वे लोग कौन हैं ? कैसे पता कीजिएगा, वह तो वहां की पुलिस की बतायेगी और अगर हमलोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लीजिए तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं उन्हीं से जॉच करवा लीजिए, गृह राज्य मंत्री बिहार के हैं उनसे जरा पूछ लें ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जा रहे हैं माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

अब ये क्या बोलेंगे बताइये न । उन्होंने कहा कि उसकी जॉच करवा लीजिए । आपका यही काम है ? आपको अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान से कोई मतलब नहीं है प्रमोद बाबू ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये ।)

जो भी सूचना हो उसको सभा पटल पर रख दिया जाय । अरे कितनी देर बोलियेगा, यही डिबेट चलेगा ? आप क्यों माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल को रोज-रोज बाधित करते हैं ? माननीय सदस्य तारकिशोर बाबू ने अपना प्रश्न पूछने के लिए श्री जिवेश कुमार माननीय सदस्य को ऑथोराइज किया है । क्या माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी । माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल के प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने श्री संजय सरावगी को ऑथोराइज किया है । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हमको 10 मिनट समय दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, जब माननीय उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे तब प्रश्नकाल नहीं चल रहा था, समय बर्बाद नहीं हो रहा था और नेता प्रतिपक्ष अगर दो मिनट बोल लेंगे तो समय बर्बाद हो जायेगा ? आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष पहले बोले और उसके क्लेरिफिकेशन के लिए संसदीय कार्य मंत्री भी बोले और उप मुख्यमंत्री भी बोले । अब दोनों तरफ से बातें हो गयी । जो भी हो मैंने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आप सदन पटल पर उसको रख दीजिए, सरकार उसको देखेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : श्री संजय सरावगी माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है कि नहीं ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : क्या एक मिनट । नेता प्रतिपक्ष और सरकार में बातें हो गयी ।

श्री संजय सरावगी : नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह जी ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-19, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह(क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी, आपके प्रश्न को योजना एवं विकास विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया है ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पहले मैं योजना में ही किया था जिसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्नकाल बाधित करने के लिए आपको कहीं से कोई इजाजत नहीं है । आपने सवाल उठाया, सरकार ने जवाब दिया । अब आप क्या चाहते हैं सो बोलिये । आप क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ? आप पहले अपने सदस्यों को सीट पर जाने के लिए कहिये । मैंने कहा कि आप सीट पर जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर चले गये ।)

लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार करने में आप ज्यादा सक्रिय नहीं होइये, राज्य की जनता आपको देख रही है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : अध्यक्ष की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : आप बोलिये बिलकुल निष्पक्षता है । शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : आज के अखबार में जमुई, मुंगेर के मजदूरों की घटना के बाद वापस आने की सूचना मिली है । जमुई मुंगेर के मजदूर आये हैं उसको बुलाकर के सच्चाई की जानकारी लीजिए, हमारे पास विडियो है रेकर्डिंग भी है । महोदय, ये जो बोले कि झूठ है, फरेब है । मैं खुली चुनौती देता हूँ एक टीम भेजिए और अगर झूठ होगा तो इसी सदन में हमलोग माफी मांगेंगे नहीं तो आपको माफी मांगना होगा । चार्टर प्लेन से केक काटने जाते हैं, आप चार्टर प्लेन से केक काटने जाते हैं और बिहार के मजदूरों की.....

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अडानी जी के प्लेन में नहीं बैठे, अडानी जी के प्लेन में नहीं बैठे हैं, अडानी जी के प्लेन में नहीं पहुंचे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : कहां से प्लेन आता है । मजदूरों की जिंदगी से ज्यादा..... महोदय, कमिटी गठित हो, स्पेशल कमिटी गठित हो । वहां के डीजीपी का बयान गलत है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जो सूचना आपके पास है उसको सदन पटल पर रख दीजिए ।

(व्यवधान)

टर्न-3/पुलकित/03.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद, अपना प्रश्न पूछें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं पूछता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके पास जो भी सूचनाएं हों उन्हें सभा पटल पर रख दें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सिर्फ भागना है ? आपका यही काम है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय इन पर कार्रवाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : अगर आप इस तरह के ज्यादा अलोकतांत्रिक काम करेंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस तरह के आचरण करने वाले लोगों को चिन्हित करके आप उन पर कार्रवाई करने के लिए रिक्मेंड कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस तरह की कार्रवाई सदन में किसी तरीके से बर्दाश्त लायक नहीं है । इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त के लायक नहीं है ।

अध्यक्ष : मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप प्रस्ताव कीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : इन्हें सदन से बाहर कीजिये । आप इन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार होइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : एकदम.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ये लोकतांत्रिक तरीके से सदन को चलने नहीं देना चाहते ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपके निदेश का पालन होगा ।

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद । मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें और शांति व्यवस्था बनाये रखें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

अध्यक्ष : जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरा देश देख रहा है, इनका असली चरित्र उजागर हो चुका है । पूरा देश और बिहार देख रहा है ।

अध्यक्ष : इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इतने महत्वपूर्ण सवाल से कोई लेना-देना नहीं है । सरकारी सम्पत्ति यानी जनता की सम्पत्ति को ये लोग तोड़-मोड़ रहे हैं लेकिन कुछ बी0जे0पी0 माईंडसेट की मीडिया यह नहीं दिखायेगी बल्कि जो सरकार के खिलाफ उलटी न्यूज होगी, उसे परोसने में लगी रहती है ।

अध्यक्ष : मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि विधान सभा में जो प्रश्नकाल होता है वह माननीय सदस्यों के लिए होता है । मीडिया कर्मी आप देख रहे हैं कि प्रश्नकाल को चाहे उसमें तारांकित प्रश्न हों, अल्पसूचित प्रश्न हों, शून्यकाल की सूचनाएं हों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो या कार्य स्थगन प्रस्ताव हो । माननीय, विरोधी दल के नेता और बी0जे0पी0 के लोग सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं । ये जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगा इस बात को आप पूरे बिहार को भेजने का काम करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो आप कह रहे थे, सही मामले में सदन में अमर्यादित व्यवहार और आचरण की सीमाएं टूटती जा रही हैं । उसमें भी कोई वजह हो, कोई कारण हो तब एक अलग बात है । ये बिना वजह ही कर रहे हैं । महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने तमिलनाडु की घटना का जिक्र किया । सरकार कल ही से दोनों सदनों में स्थिति बता रही है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है, जो वीडियो चल रहा है । घटना क्या है वह अभी तक किसी को मालूम नहीं है । जो वीडियो चल रहा है उसका संज्ञान लेते यहां के डी0जी0पी0 को निदेश दिया गया, तमिलनाडु के डी0जी0पी0 से सम्पर्क करके वस्तुस्थिति का एक प्रतिवेदन लेने के लिये । माननीय उप मुख्यमंत्री ने अभी आपके सामने जो डी0जी0पी0, तमिलनाडु का प्रतिवेदन आया है, उसको पूरा पढ़कर सुना दिया । इसके बाद भी हमने कह दिया और उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसके बावजूद अगर नेता प्रतिपक्ष को या सदन के किसी माननीय सदस्य को बिहार के किसी मजदूर या किसी आदमी की तमिलनाडु में फंसे होने की सूचना मिलती है तो कृपया उसका मोबाईल नंबर, वह व्यक्ति कहां है तमिलनाडु में, चेन्नई में है या दूसरे किसी ग्रामीण क्षेत्र में है उसका पूरा पता दे दीजिये । सरकार तुरंत आगे की कार्रवाई करेगी । महोदय, जरा सोचिये अब इसके बाद क्या बचता है । इसके बाद अगर कुछ बात होती है तो इसका तो सीधा अर्थ है कि इनको न मजदूरों से हमदर्दी है और न बिहार की इज्जत से कोई मतलब है । मतलब है तो सिर्फ राजनीति से है । उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वीडियो है इसकी सत्यता स्वयं डी0जी0पी0 ने लिखकर दी है कि वह वीडियो पहले की है । दोनों घटनाओं के बारे में बता दिया कि वे दोनों घटनाएं अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में काफी पहले घटी हैं । अब इसको शरारतपूर्ण तरीके से अभी चलाकर, जानबूझकर बिहारी भावना को उकसाकर दो राज्यों के बीच संबंध बिगाड़ने की इससे बड़ी बे-मतलब चीज क्या हो सकती है । आखिर न कोई बात है, न कोई घटना है और सरकार कह रही है कि आप दीजिये । महोदय, कल भी हमने उस सदन में कहा था और ये बात-बात

में जोड़ देते हैं कि उप मुख्यमंत्री वहां गये थे । उप मुख्यमंत्री तो उनके व्यक्तिगत आमंत्रण पर गये थे, स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन था, उस पर वे एक कार्यक्रम कर रहे थे । उन्होंने व्यक्गित रूप से आमंत्रण देकर बुलाया, उप मुख्यमंत्री जी उसमें गये थे । इन दोनों घटनाओं को जोड़ने का क्या मतलब है ? अगर वहां पर कोई घटना घट गयी तो सरकार किसी कारण से यहां के अधिकारी या मंत्री तमिलनाडु नहीं जायेंगे क्या ? ये क्या-क्या बात, कहने का मतलब है कि इनको न मजदूरों से हमदर्दी है, न बिहार की अस्मिता, इज्जत से कोई हमदर्दी है । इनको सिर्फ किसी घटना, दुर्घटना, आकस्मिकी में या इस तरह के फरेबी, शरारतपूर्ण समाचार के पीछे अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने की आदत है । महोदय, जिसको बिहार की जनता अच्छे तरीके से देख रही है, जान रही है, पहचान रही है ।

महोदय, हम यह जरूर कहेंगे कि सदन में जिस तरह का आचरण किया जाता है बिना किसी उकसावे के । आप देखते रहते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष के सातों दल के सभी माननीय सदस्य आपके निदेशानुसार अनुशासित तरीके से बैठे रहते हैं और आप ही के नियमन के विरूद्ध उधर के लोग ही क्या-क्या करने लगते हैं, यहां पर टेबल पटकने लगते हैं, कुर्सियां उछालने लगते हैं । इस तरीके से सदन में अव्यवस्था बिना वजह फैलायी जायेगी ? यह तो सदन के लिए समझिये सदन को अपमानित करने की बात है । कोई उस तरह की उत्तेजना की बात हो तो तब बात समझ में आती है । ये तो लगता है जैसे नियोजित ढंग से सोचकर ही आते हैं कि सदन में जाते ही यही सब करना है । इसलिए महोदय, इसका आसन ने जो गंभीरता से संज्ञान लिया है, सरकार आसन के संज्ञान लेने के साथ है और जो भी आसन का आदेश होगा, जो भी आसन से निदेश आयेगा, सरकार उसमें सहयोग करेगी लेकिन इस तरह के अमर्यादित या सदन को अपमानित करने के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय.....

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज प्रसाद । माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

प्रश्न काल होने दिया जाए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक बात सुन ली जाए.....

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-20, डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : 1- बिहार में 63 प्रतिशत महिलाएं और 69 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रसित है । इसके कारण निम्न हो सकते हैं:-

आयरन की प्रचुरता वाले आहार कम लेना या नहीं लेना, परिवार मे लिंग भेद के कारण पर्याप्त और उपयुक्त भोजन ना मिल पाना, भोजन में फॉलिक एसिड, विटामिन-सी, विटामिन बी-12 की कमी, विटामिन-सी युक्तफल के सेवन का प्रचलन नहीं होने के कारण शरीर में आयरन के अवशोषण में कमी होना । यह सब आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के प्रमुख कारण है ।

गैर पोषण जनित एनीमिया भी हमारे समुदाय मे पाया जाता है जिसके प्रमुख कारण है पेट मे कृमि होना, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फलोरोसिस रोग होना, मलेरिया एवं कम उम्र में विवाह तथा गर्भधारण भी एनीमिया के कुछ गैर पोषण जनित कारण है ।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत् 06 से 59 माह के बच्चों को सप्ताह में दो बार आई0एफ0ए0 सिरप ऑटो डिस्पेंसर के माध्यम से आशा के द्वारा गृह भ्रमण के दौरान दिया जा रहा है, साथ ही समेकित बाल विकास परियोजना (समाज कल्याण विभाग) अन्तर्गत अन्न प्राशन दिवस पर भी 6 माह के शिशु को ऊपरी आहार के साथ आई0एफ0ए0 सिरप भी दिए जाने का प्रावधान शुरू किया गया है । गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 180 लाल आई0एफ0ए0 की गोली वी0एच0एस0एन0डी0 पर ए0एन0एम0 के माध्यम से एवं सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में देने का प्रावधान है ।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। लोगों में जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। आँगनवाड़ी सेविका, ए0एन0एम0, आशा द्वारा माताओं को आयरन सिरप एवं गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली से संबंधित परामर्श दिया जाता है । इस हेतु आशा को अपने पोषण क्षेत्र में 06 से 59 माह के बच्चों को सप्ताह में दो बार आई0एफ0ए0 सिरप पिलाने पर सौ रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

इस संबंध में आपूर्ति श्रृंखला को भी सुदृढ़ किया गया है । प्रखण्ड स्तर पर अबतक दवा की माँग ऑनलाईन माध्यम डी0वी0डी0एम0एस0 से की जा रही है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार 22.9 फीसदी बच्चे दुबलापन के शिकार हैं, जिसे कम करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित हैं -

नवजात शिशु की घर पर देखभाल- आशा द्वारा माता एवं शिशु की घर पर देखभाल हेतु जन्म से 42 दिनों तक निर्धारित अंतराल पर स्वस्थता की निगरानी करना छः माह तक सिर्फ स्तनपान हेतु परामर्श देना एवं आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्थान में जाने के लिए प्रेरित करना है ।

पोषण पुनर्वास केन्द्र - जन्म से 60 माह तक के चिकित्सकीय जटिलतायुक्त गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु राज्य के 37 जिलों एवं एक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 20 शैय्या वाले एवं 3 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 10 शैय्या वाले पोषण पुनर्वास केन्द्र का संचालन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम- कार्यक्रम अन्तर्गत बच्चों को कृमि मुक्त करने हेतु राज्य के 1-19 वर्ष तक के बच्चों को अलबेन्डाजोल (400 एम0जी0) की निःशुल्क गोली (उम्र के अनुसार) खिलाने का प्रावधान है । इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है ।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा- प्रति वर्ष मानसून से पूर्व सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है । पखवाड़ा के दौरान पाँच वर्ष तक के बच्चों वाले घरों में आशा द्वारा ओ0आर0एस0 पैकेट का निःशुल्क वितरण किया जाता है एवं दस्त से बचाव तथा उपचार से संबंधित जानकारी माता-पिता को दी जाती है ।

माँ/आई0वाई0सी0एफ0 (IYCF\MAA)- नवजात शिशु को जन्म के एक घंटा के भीतर एवं छः माह तक सिर्फ स्तनपान कराने एवं छः माह के पश्चात् उम्र के अनुसार पूरक आहार दिये जाने के संबंध में गर्भवती महिला एवं धात्री माता को जानकारी देने एवं प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में ''माँ'' कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है । आशा द्वारा छोटे समूहों में गर्भवती एवं धात्री माताओं के साथ बैठक आयोजित कर उपरोक्त जानकारी प्रदान की जाती है ।

गृह आधारित छोटे बच्चों की देखभाल (Home Based Care for Young Child-HBYC) कार्यक्रम- बाल्यकाल में होने वाली मृत्यु/बीमारियों (जैसे निमोनिया, डायरिया इत्यादि) एवं कुपोषण से बचाव करते हुए उनका शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु शिशुओं की 3, 6, 9, 12 एवं 15 माह की आयु पूर्ण होने पर आशा द्वारा गृह भ्रमण की जाती है । इसके तहत् आशा द्वारा छः माह तक केवल स्तनपान छः माह से संपूरक आहार तथा कम से कम 2 वर्ष तक नियमित स्तनपान जारी रखना, आयरन एवं फोलिक एसिड सिरप का अनुपूरण आदि का उपयोग, बच्चों हेतु उम्र आधारित खेल एवं संचार सही तरीके से हाथ धोने की

विधि का अभ्यास एवं अन्य स्वच्छता व्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु परामर्श प्रदान की जाती है । वर्त्तमान में राज्य के 20 उच्च प्राथमिकता जिलों (High Priorty) में क्रियान्वित किया जा रहा है ।

टर्न-4/अभिनीत/03.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को यह सुझाव देते हुए कि सरकार अगर यह कार्यक्रम चला रही है और हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार अपनी मैकेनिज्म को इतना डेवलप करेगी कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें? और जहां तक सवाल है, 2015-16 में जो आकड़े थे, एन0एच0एस0 के जो आंकड़े थे उससे आज भी हमारे आंकड़े टेली कर रहे हैं, तो ये 2015-16 और 2023 में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं तो इसका मतलब यह होता है अध्यक्ष महोदय कि कार्यक्रम तो चलाये जा रहे हैं, पेपर पर कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन जो अचीवमेंट आनी चाहिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पूरक प्रश्न क्या है ? पूरक प्रश्न पूछिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यही है, माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या सरकार कोई और मैकेनिज्म लेकर आना चाहती है ? अपने को इम्प्रूव करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक गंभीर सवाल पूछा है और सदस्य की चिंता भी जायज है । हमने पूर्व में उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया कि बीमारी का कारण क्या है और इसके लिए सरकार क्या-क्या कार्यक्रम किस-किस माध्यम से, चाहे दवा वितरण का हो, जांच की हो या जो प्रोत्साहन राशि लोगों को दी जाती है, इस कार्यक्रम में जो सरकार के लोग लगे रहते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए हमलागों का एक रोडमैप तैयार है और जाहिर सी बात है कि आपने जो सवाल पूछा है, प्रतिशत जो है, औसत जो है, चिंता जो आपकी है कि यह बीमारी कम होनी चाहिए । वैसे सरकार भी गंभीर है, चिंतित है और इसको देखते हुए हमलोग, सबलोग अगर अलग से भी कुछ सुझाव आपके पास होंगे और विभाग में भी इस बात को लेकर चर्चा हमलोग करेंगे कि अगर और कोई कार्यक्रम चलाना हो या कोई एस्पेक्ट होगा इससे रिलेटेड तो उनसे भी वार्ता करके, सुझाव प्राप्त करके उस हिसाब से और भी योजना हमलोग लाने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र सं0–138, विभूतिपुर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1–उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2–वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित विज्ञापन में उल्लेखित नियम एवं शर्त भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन0सी0आई0एस0एम0) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन प्रावधान के अनुरूप नहीं थी । एन0सी0आई0एस0एम0 के अद्यतन प्रावधान के अनुरूप बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक) शिक्षण सेवा संवर्ग नियमावली, 2017 में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जा रही है । तत्पश्चात् विज्ञापन में नियमानुसार विभागीय सहमति शीघ्र संसूचित कर दी जायेगी ।

3– उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार : माननीय मंत्रीजी से सिर्फ इतना...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय कुमार : पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं महोदय ।

अध्यक्ष : सिर्फ एक पूरक प्रश्न ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बस एक पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं । महोदय, विज्ञापन में संशोधन और संसूचित करने की जो बात कही गयी है, यह कबतक हो जायेगा बस इतना ही बता दिया जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने साफ रूप में कहा है कि जो शिक्षण सेवा संवर्ग नियमावली, 2017 है में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जा रही है । उसके पश्चात् विज्ञापन के नियमानुसार विभागीय सहमति शीघ्र संसूचित करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–533 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र सं0–239, वारिसलीगंज)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–534 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0–20, चिरैया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–535 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र सं0–6, नौतन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-536 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र सं0-169, शेखपुरा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्ष 2013 से वितरण कम्पनी में 24X4 ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के कार्य हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के द्वारा एजेन्सी के कर्मी (मानवबल) से कार्य लिया जाता रहा है ।

2- अस्वीकारात्मक है । आउटसोर्सिंग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों (मानवबल) को बिहार सरकार के श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मासिक मजदूरी का भुगतान एजेन्सी के द्वारा किया जाता है । न्यूनतम मासिक मजदूरी की गणना एवं भुगतान निर्धारित कार्य दिवस के आधार पर की जाती है । मानवबल उपलबध कराने के मद में संबंधित कम्पनी द्वारा एजेन्सी को कमीशन के रूप में अलग से भुगतान किया जाता है ।

3- आउटसोर्सिंग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मी (मानवबल) को श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एजेन्सी के द्वारा किया जाता है । बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के वृद्धि किये जाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे एजेन्सी के कर्मी (मानवबल) को न्यूनतम मासिक मजदूरी में वृद्धि होती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर उपलब्ध है, पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि 30 दिन काम करने के बाद भी 26 दिन का भुगतान उचित है या नहीं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसमें स्पष्ट लिखा है कि श्रम विभाग का जो कानून है, उसी के हिसाब से इन मजदूरों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं । श्रम विभाग के कानून के अनुरूप ।

श्री विजय कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि सरकार मानक बल के वेतन वृद्धि के साथ थर्ड पार्टी से विभाग अपने अधीन लेकर नियमित बहाली कबतक कराना चाहती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नियमित बहाली का कोई प्रश्न नहीं है और वेतन बढ़ाने का तो मैंने कहा कि श्रम विभाग के अनुरूप ही दिया जाता है । ये चूंकि स्थायी नहीं हैं, अस्थायी तौर पर इनसे काम लिये जाते हैं, इसलिए नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-537 (श्री अशोक कुमार चौधरी, क्षेत्र सं0-92, सकरा(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–538 (श्रीमती नीतु कुमारी, क्षेत्र सं0–236, हिसुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ विधानसभा के तीन प्रखण्ड यथा हिसुआ, नरहट एवं अकबरपुर की विभिन्न पंचायतों से होकर पांच अद्द कृषि फीडर गुजरते हैं । उपर्युक्त पंचायतों से कृषि विद्युत संबंध हेतु कुल 1211 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं 973 अद्द आवेदकों को परियोजना के आकार के अनुरूप विद्युत संरचना स्थापित कर कृषि विद्युत संबंध प्रदान कर दिए गए हैं । शेष आवेदकों को आगामी परियोजना आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत विद्युत संरचना का निर्माण कर कृषि विद्युत संबंध प्रदान कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको उत्तर भेजा गया है, आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, हमारा जिला पिछड़ा हुआ जिला है और वहां बहुत जगहों से शिकायत मिली है कि खेती वाला जो ट्रांसफॉर्मर है वह कहीं–कहीं नहीं लगा है । महोदय, इसको लगवाने की कृपा की जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, टेंडर कर दिया गया है, जो बचे हुए लोग हैं उनका कनेक्शन भी जल्द ही अप्रैल–मई से प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सरकार बिल्कुल तत्परता से कार्य कर रही है । माननीय सदस्या, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या–539 (श्री राजेश कुमार, क्षेत्र सं0–222, कुटुम्बा (अ0जा0))

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से विभागीय पत्रांक–489, दिनांक– 01.03.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में पूर्ण विवरणी नक्शा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं निर्माणोपरांत रख–रखाव व्यवस्था सहित अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटकीय मापदण्डों यथा पर्यटकों की संख्या, पर्यटकीय विकास की संभावनाएं तथा निधि की उपलब्धता आदि के आलोक में अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा ।

टर्न–5/हेमन्त/03.03.2023

श्री राजेश कुमार : बस एक ही पूरक पूछेंगे महोदय । ये बुढ़ा–बूढ़ी बांध गया जिला से जोड़ता है और इसमें इतना सौंदर्य है, सरकार का मैं आभारी हूं, पिछली सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी बुढ़ा–बूढ़ी बांध 368 करोड़ की लागत से बनवाया गया

है । इसलिए इसमें हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि इसकी समय-सीमा निर्धारित कर दें, तो बड़ी कृपा होगी सरकार की भी और सदन की भी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो जिला पदाधिकारी को विभाग ने लिखा है, जब पूरी रिपोर्ट आ जायेगी, तो उसके आधार पर...

अध्यक्ष : सरकार ने अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : सारी चीजें बता दी हैं । पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटकीय मापदंडों यथा पर्यटकों की संख्या, पर्यटकीय विकास की संभावनाएं तथा निधि की उपलब्धता के आलोक में ही निर्णय लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-540(श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0-195, अगिआंव(अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, आरा में हड्डी के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है । सदर अस्पताल, आरा में तीन हड्डी रोग विशेषज्ञ क्रमशः डॉ0 महावीर प्रसाद गुप्ता, डॉ0 राज नारायण यादव एवं डॉ0 अमन पदस्थापित हैं ।

कर्तव्यहीनता के आरोप में डॉ0 शिव कुमार प्रसाद, नेत्र चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ।

वर्तमान में सदर अस्पताल, आरा के नेत्र शल्य कक्ष के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण आंख का ऑपरेशन स्थगित है । तीन माह के अन्दर नेत्र शल्य चिकित्सा पुनः प्रारम्भ किये जाने की योजना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको प्रश्न का जवाब मिल गया है । कृपया पूरक पूछिये ।

श्री मनोज मंजिल : जी, पूरक पूछता हूं । महोदय, सदर अस्पताल, आरा में आंख का ऑपरेशन करने वाले तीन मास्टर सर्जन की पोस्ट हैं जिसमें एक भी डॉक्टर नहीं है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाली माइक्रोस्कोप मशीन नहीं है, नर्स, स्टाफ, ओ0टी0 है ही नहीं और स्कैन मशीन भी खराब पड़ी है । और हड्डी के मामले में जवाब आया है कि ऑपरेशन होता है, लेकिन जब वहां डेडिकेडिड ऑर्थोपेडिक ओ0टी0 नहीं है, स्टाफ नहीं है, जब वहां ट्रेक्शन टेबल नहीं है, कुल्हों का ऑपरेशन, हड्डियों में स्टील नहीं डाला जाता है, ओपन सर्जरी नहीं होती है, तो जो डॉक्टर होते हैं, अपना स्टाफ और अपना स्ट्रूमेंट लाकर ऑपरेशन करते हैं, तो मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या मास्टर ऑपरेशन आंख का ऑपरेशन करने वाले और ओ0टी0 आंख का बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी जो माइक्रोस्कोप मशीन वहां आयेगी कि नहीं आयेगी और हड्डी का ऑपरेशन करने के लिए डेडिकेडिड

ओ0टी, वहां सी0आर0एम0 मशीन सदर अस्पताल में 15 लाख रुपये में खरीदी गयी है, लेकिन उसका रख-रखाव नहीं है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री मनोज मंजिल : महोदय, डेडिकेटेड हड्डी का ओ0टी0 बने, ट्रेक्शन टेबल और जो ऑपरेशन करने वाला मेडिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स होता है, वह इन्स्ट्रूमेन्ट्स और स्टाफ वहां पर कब तक आ जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्य को जवाब भेजा गया था, वहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ0 महावीर प्रसाद गुप्ता, डॉ0 राज नारायण यादव एवं डॉ0 अमन पदस्थापित हैं और कर्तव्यहीनता के आरोप में डॉ0 शिव कुमार प्रसाद, नेत्र चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और वर्तमान में सदर अस्पताल, आरा के नेत्र शैल्य कक्ष के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है यानी जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है जिसके कारण आंख का ऑपरेशन स्थगित है । ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन अभी नवीनीकरण कार्य चल रहा है । फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं या मशीन और इक्विपमेंट चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार करायेगी । क्योंकि हड्डी और आंख का तो वहां पर करना ही है ।

श्री मनोज मंजिल : मंत्री महोदय, आपसे एक विनम्र आग्रह है कि वहां पर 15-20 सालों से आंख का ऑपरेशन होता ही नहीं है, मैं यह कह रहा हूं । क्योंकि जिस डॉक्टर पर कार्रवाई हो रही है वह मास्टर सर्जन नहीं है, वह डिप्लोमा डिग्री वाले हैं । वह सर्जरी नहीं करते । वहां पर तीन पोस्ट हैं, लेकिन वहां पर मास्टर सर्जन है ही नहीं। ओ0टी0 नहीं है, नर्स, स्टाफ और माइक्रोस्कोप मशीन जब नहीं है, जिससे ऑपरेशन होता है, लैंस की पावर बताने वाली स्कैन मशीन खराब है, तो ऑपरेशन कैसे होता है महोदय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वहां पर नवीनीकरण का कार्य हो रहा है, लेकिन हम वहां के प्रभारी मंत्री हैं, तो एक बार पर्सनली रिव्यू हम भी कर लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-541(श्री विजय कुमार, क्षेत्र सं0-169, शेखपुरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : 1- स्वीकारात्मक ।

2- जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन में भूमि आदि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । भूमि से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत

पर्यटकीय संभावनाओं एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा । पर्यटन विभाग द्वारा किसी पर्यटक स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की कार्रवाई नहीं की जाती है ।

3- खंड-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही सकारात्मक जवाब दिया है । साथ ही, इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । तो मैं अनुरोध करता हूं कि पुनः जिला पदाधिकारी को जमीन संबंधित विवरण हेतु आदेश निर्गत करने की कृपा करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन में भूमि आदि का स्पष्ट उल्लेख नहीं था । तो इसको लेकर संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत हमारा विभाग वहां के जिलाधिकारी से बात करेंगे, भूमि उपलब्ध होगी तो उसके बाद, लेकिन पर्यटन स्थल का दर्जा देने की कार्रवाई हमारा विभाग नहीं करता है ।

तारांकित प्रश्न सं0-542(श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-543(श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-166, जमालपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 101(10), दिनांक- 07.01.2023 एवं पत्रांक- 112(10), दिनांक- 09.02.2023 तथा पत्रांक-270(10), दिनांक- 02.03.2023 के द्वारा जल संसाधन विभाग से भूमि हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, जो प्रक्रियाधीन है । इसके प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जवाब आपको प्राप्त है । आप पूरक पूछें ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक- 1/1016/540, दिनांक-12.03.2022 को सरकार के अवर सचिव के पास जमालपुर में कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर के लिए जमीन जो चिन्हित की गयी थी, उसके लिए कहा गया था कि आप विभागीय स्तर पर आप अनापत्ति दें । उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी महीने में, फरवरी महीने में और मार्च के महीने में भी जल संसाधन विभाग से भी भूमि हस्तांतरण हेतु अनापत्ति पत्र मांगा है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि

आप पहल करके जल संसाधन से इस तथाकथित जमीन को कम्यूनिटी हेल्थ के लिए अविलंब अनापत्ति पत्र दिलवाने का काम करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सदस्य के सवाल को लेकर हमारा विभाग तो गंभीरता दिखा रहा है । सदस्य ने भी बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में लगातार हम लोगों ने इरीगेशन डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है । अनापत्ति पत्र जब प्राप्त हो जायेगा, तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-544(श्री पवन कुमार यादव, क्षेत्र सं0-155, कहलगांव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-545(श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, क्षेत्र सं0-10, रक्सौल)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-546(श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र सं0-62, पूर्णिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-547(श्री हरि नारायण सिंह, क्षेत्र सं0-177, हरनौत)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : खंड-1 स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-240(7), दिनांक-28.10.2022 के आलोक में विधान सभा वार माननीय सदस्य की अनुशंसा पर संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी के माध्यम से स्थल चयन कर नये भवन के निर्माण हेतु प्रतिवेदन की मांग की गई है । इसके प्राप्त होने के पश्चात विहित प्रक्रियानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

श्री हरि नारायण सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त है, मैं पूरक पूछना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब है उसमें है कि माननीय विधायकों द्वारा सात-सात स्वास्थ्य उपकेंद्र की अनुशंसा करनी थी, मैंने अनुशंसा दे दी । लेकिन प्रश्नगत इस मामले में है कि चौरासी नालंदा जिला के नगरनौसा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दामोदरपुर बलधा के अंतर्गत आपका जो चौरासी में उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसके नाम की मैंने अनुशंसा नहीं की । 35 साल पूर्व का भवन बना हुआ है । भवन ध्वस्त है । तो क्या सरकार इस भवन को तोड़कर नया भवन बनाना चाहती है ? चूंकि मेरी अनुशंसा नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक-240(7), दिनांक-28.10.2022 के आलोक में विधान सभा वार माननीय सदस्य की अनुशंसा पर संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी के माध्यम से स्थल चयन कर नये भवन के निर्माण

हेतु नये प्रतिवेदन की मांग की गयी है । इसके पश्चात ही हम लोग प्रक्रियानुसार निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक और पूरक है कि मैंने जो अनुशंसा दी, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरासी है, की मैंने अनुशंसा नहीं की है, इसीलिए मैंने प्रश्न डाला तो क्या यह जो प्रश्नगत स्वास्थ्य उप केन्द्र है, इसको भवन तोड़कर निर्माण करा देंगे ?

टर्न-6/धिरेन्द्र/03.03.2023

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अभी ऐसी कोई बात है नहीं, जो जवाब है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है । अगर माननीय सदस्य जिसकी अनुशंसा करना चाहते हैं तो वह बता दिया जाय ।

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्तर से सात जीर्ण-शीर्ण भवनों की अनुशंसा कर दिया है । अगर इस अनुशंसा में आता तो मैं प्रश्न ही नहीं करता चूंकि प्रश्न मुझे इसलिए करना पड़ा कि वे जो सात-सात उप स्वास्थ्य केन्द्र का अनुशंसा करना था वह मैंने कर दिया, उन सातों अनुशंसा में यह नहीं है तो क्या इस परिस्थिति में 84 स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन को तोड़ कर बनाना चाहती है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, तोड़ कर बनाने का नहीं है लेकिन आपकी जो अनुशंसा है, उसे एक बार फिर से भिजवा दीजिये या दे दीजिये, उसको हमलोग देखते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-548 (श्री सुदामा प्रसाद, क्षेत्र संख्या-196, तरारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मोपती ग्राम में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्य लंबित है ।

विषय की गंभीरता को देखते हुए विभागीय पत्रांक-260(10), दिनांक-01.03.2023 के द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर से इसका निष्पादन शीघ्र कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछें ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ । वहाँ पर जमीन है और संवेदक भी बहाल हो गए हैं लेकिन सी॰ओ॰ तीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों का एन॰ओ॰सी॰ नहीं दे रही है और कोई भी क्षेत्र विकास योजना के लिए जब हमलोग लिखते हैं तो

वह बराबर अगर–मगर लगा देती हैं । वहाँ पर जमीन है और संवेदक भी बहाल हो गए हैं । यह पूरे बिहार का मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ है तो जमीन के कागजात या रजिस्ट्री के साथ जमीन हमें उपलब्ध करा दें, हम दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बहुत अच्छा जवाब दिये । आप उन्हें उपलब्ध करा दीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । माननीय सदस्य की जो भी योजनाओं की अनुशंसा जाती है, उस अनुशंसा के आलोक में सी॰ओ॰ को एन॰ओ॰सी॰ देना है लेकिन वह टाल रहा है, नहीं मिल रहा है । हम मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अनुशंसा किये हैं वह भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है जिसके कारण एक साल से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय पर रहिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यह अंचलाधिकारी से संबंधित मामला है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अंचलाधिकारी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरा प्रश्न यही है कि ऐसे अधिकारी जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी और एक निश्चित समय में कार्रवाई हो ?

अध्यक्ष : सरकार ने अपने स्तर से जो कार्रवाई की उसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी दे दी गयी और...

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है, उसका इतना पॉजिटिव उत्तर है लेकिन जब तक एन॰ओ॰सी॰ नहीं आयेगा तब तक विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है । आपका जो सवाल सी॰ओ॰ को लेकर है तो वह अलग विषय है लेकिन फिर भी मैंने पहले कहा कि अगर जमीन उपलब्ध है तो उसका कागजात, रजिस्ट्री के साथ दिखाइयेगा तो हमलोग देखेंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, इसकी जाँच करायी जाय कि सी॰ओ॰ जो लिखी हैं कि जमीन नहीं है तो इसकी जाँच माननीय मंत्री जी करवा सकते हैं ? जाँच करवाइये और उन पर कार्रवाई की जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : आप लिखित में हमें उपलब्ध करा दें चूँकि विषय अलग है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, उप स्वास्थ्य केन्द्र से ही संबंधित है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमारा काम है कि जमीन उपलब्ध हो जाय तो उस पर काम करना ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, वहाँ जमीन है तो सी॰ओ॰ एन॰ओ॰सी॰ क्यों नहीं दे रही है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : ठीक है, तो बता दीजिये हम कर देंगे और अलग से कोई बात या शिकायत है तो उसे लिखित में दे दीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी लिखित माँग रहे हैं तो उन्हें लिखित दे दीजियेगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इससे संबंधित नहीं है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सत्यदेव बाबू, प्रश्नकर्ता खड़े हुए, सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, फिर प्रश्नकर्ता बैठ गए, फिर आप सप्लीमेंट्री पूछे, उसके बाद उन्होंने पूछा और सरकार ने जवाब दिया । अब आप ही सोचिये कि इस प्रश्न पर कितना समय गंवाइयेगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हमने उप मुख्यमंत्री जी से पूछा है कि अंचलाधिकारी इस तरह की हरकत करता है तो उनके ऊपर कौन-सी कार्रवाई कीजियेगा ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि लिखित में दीजियेगा तब तो हम कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : आपसे लिखित मांग रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम कहाँ मना कर रहे हैं, और हम वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं अगर कोई गड़बड़ करेगा तो छोड़ा थोड़े ही न जायेगा ।

अध्यक्ष : ये तो और बढ़िया बात है कि स्वास्थ्य मंत्री आरा के कार्यान्वयन के प्रभारी मंत्री भी हैं । आपलोग आमने-सामने बैठ कर निदान करा लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-549 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र संख्या-67, मनिहारी (अ॰ज॰आ॰))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-550(श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, क्षेत्र सं0-200, बक्सर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जवाब तो दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जवाब मिल गया है तो आप पूरक पूछें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : नहीं मिला है तो माननीय ऊर्जा मंत्री, आप जवाब पढ़ दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला में कैम्प एवं सुविधा ऐप के माध्यम से कृषि विद्युत संबंध हेतु कुल 14850 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7404 आवेदकों को परियोजना के आकार के अनुरूप विद्युत संरचना का निर्माण कर कृषि विद्युत संबंध प्रदान कर दिया गया है । शेष आवेदकों को

आगामी परियोजना आर॰डी॰एस॰एस॰ के अंतर्गत विद्युत संरचना का निर्माण कर जून, 2024 तक कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिना भूमिका बनाये पूरक पूछें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक में यह कहना है कि माननीय मंत्री जी वर्ष 2024 का लक्ष्य दिये हैं जबकि किसानों ने अपने आवेदन के साथ ऑनलाईन या ऑफलाईन में अपनी राशि भी जमा कर दी है और वे लोग पोल के लिए बाँस और तार का प्रयोग कर रहे हैं, इससे किसानों के जान-माल का खतरा है और विभाग को भी खतरा है तो मैं यह चाहता हूँ कि जो चार हजार आवेदक बचे हुए हैं उनको धान के फसल के पहले, ऑनलाईन या ऑफलाईन जो आवेदक आवेदन दिये हैं उनको बिजली संबंधित कार्रवाई करने का निर्देश माननीय मंत्री जी दे दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि आवेदन दिए गए थे लेकिन बीच में कोरोना आ गया, काम बंद हो गया था इसलिए देरी हुई । अब फिर से उसका टेंडर हुआ है और वर्ष 2024 तक कुल करने का है, अप्रील महीने से कन्टीन्यूअस काम शुरू हो जायेगा और इसको फेज वाइज किया जायेगा ।

अध्यक्ष : सरकार ने बिल्कुल सक्षम तरीके से आपके प्रश्न का जवाब दिया और सरकार कार्रवाई कर रही है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । एक मिनट मेरी बात सुन ली जाय, इससे विभाग को भी खतरा है और हमारे किसानों को भी खतरा है । अध्यक्ष महोदय, आये दिन ऐसी घटनाएँ होती हैं कि तार टूट कर गिर जाता है और पटवन के लिए किसान जाते हैं और वह मारे जाते हैं तो मेरा यह कहना है कि पूरे बिहार में वैसे किसानों को, मैं बक्सर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ । माननीय मंत्री जी, ये विद्युत कनेक्शन पोल और तार के जरिए दिलाने की कृपा प्रदान करें ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब स्थान ग्रहण किया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-551 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र संख्या-6, नौतन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-552 (श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-16, कल्याणपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-553 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र संख्या-208, सासाराम)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सासाराम के पत्रांक–499, दिनांक–23.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत नवनिर्मित वार्ड एवं पुराने वार्ड में आई॰पी॰डी॰एस॰ योजनांतर्गत कुल 57,499 किलोमीटर जर्जर तार ए॰बी॰ केबल के द्वारा बदल कर विद्युत संरचना को सुदृढ़ किया गया है । पुराने वार्ड में कुछ संकरी एवं तंग गलियों तथा नए वार्डों में जर्जर तार बदलने का कार्य लंबित है जिसे आगामी आर॰डी॰एस॰एस॰ योजना में शामिल कर लिया गया है । एजेंसी चयन का कार्य प्रक्रियाधीन है । मार्च, 2023 तक कार्यादेश निर्गत करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सासाराम नगर निगम अंतर्गत जगह–जगह बिजली का नंगा तार लटका रहता है । मेरा माननीय मंत्री जी से कहना था कि उसको कवर तार कब किया जायेगा ? आये दिन कोई–न–कोई घटना होते रहती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कवर तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अगर कोई कठिनाई या दिक्कत होती है तो माननीय सदस्य लिख कर दें, मैं उसको दिखवा लूँगा ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया गया है कि 57,499 किलोमीटर तार को कवर किया गया है लेकिन शहर में यह कहीं दिखता नहीं है और अगर किया भी गया है तो लगभग जगह नंगा तार लटका रहता है जिससे आये दिन कोई–न–कोई घटना होते रहती है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह कब तक हो जायेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है और यहाँ लिखा हुआ है कि हो गया है तो मैं दिखवा लूँगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसे दिखवा लेंगे, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, धन्यवाद ।

टर्न–7/संगीता/03.03.2023

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुए । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-03 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है :

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजय सरावगी, श्रीमती रश्मि वर्मा । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-171(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिए जायेंगे ।

शून्यकाल

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को BPL छात्रों के लिए देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान वर्ष 2017-18 से लम्बित है, जिससे निजी विद्यालयों के प्रबंधन को कठिनाई हो रही है।

अत: मैं इस विषय पर सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल विधान सभा के अरवल अंचल सहित बिहार के विभिन्न अंचलों में अंचलाधिकारी का पद रिक्त है । लेकिन बिहार सरकार पदस्थापन की प्रतीक्षा में दर्जनों अंचलाधिकारी को सचिवालय में बैठाकर न तो वेतन देती है न तो पदस्थापन करती है । इसलिए अंचलाधिकारी के पदस्थापन के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत नगर परिषद शेरघाटी के शेखपुरा मोड़ से भटकुरहा मोरहर नदी पुल तक जर्जर सड़क की मरम्मती कराने की मांग करती हूं।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत मेडिकल कॉलेज नहीं रहने के कारण किशनगंज जिला के छात्र/छात्राओं को मेडिकल साईंस की शिक्षा लेने दरभंगा जिला में जाना पड़ता है, जिसके कारण समय एवं आर्थिक हानि होती है ।

अत: किशनगंज जिला में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य में बिजली बिल से संबंधित मामलों को अपराध की श्रेणी से अलग रखा जाय । पूर्व से बकाए बिजली बिलों में से ब्याज की राशि को कम से कम एक बार माफ करने की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ0 बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की एम्स, फुलवारी शरीफ गोलम्बर पर आदम कद प्रतिमा लगाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड-भभुआ, पंचायत-महुआरी, ग्राम-अमाढ़ी में फील्ड के लिए काफी जमीन उपलब्ध है, उबड़-खाबड़ जमीन होने के कारण दर्जनों गांवों के बच्चों को खेल में अपनी प्रतिभा निखारने में काफी कठिनाई होती है ।

उक्त मौजा में मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधान सभा अन्तर्गत बरौनी प्रखंड के पिपरा देवस चौक से भगवानपुर प्रखंड जाने वाली सड़क की चौड़ाई दस फीट से भी कम है ।

अतः दो प्रखंडों को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बीरेन्द्र कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला के परैया प्रखण्ड अन्तर्गत पुनाकला पंचायत में लोडहर ग्राम के समीप से जाने वाली नहर पर पुल निर्माण कराना जनहित में अति आवश्यक है ।

अतः मैं राज्य सरकार से उक्त पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभिन्न उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरियों को महीनों और वर्षों से वेतन नहीं मिलने के कारण इनकी स्थिति दयनीय हो गई है ।

रात्रि प्रहरी का वेतन बढ़ाया जाए तथा मासिक वेतन का पैसा जिला से सीधे इनके खाते में भेजने की व्यवस्था की जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रणब कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुण्ड प्रखण्ड के मरचिनमा मोड़ के पास योगिया नाला में छिटका सह पुलिया निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुरारी मोहन झा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में CTET एवं STET पास अभ्यर्थीगण सातवें चरण की बहाली हेतु सरकार से मांग कर रहे हैं किंतु शिक्षक बहाली का मामला अभी कैबिनेट में रूका हुआ है ।

अत: मैं सरकार से यथाशीघ्र सातवें चरण की शिक्षक बहाली की मांग करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री रामबलि सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, घोसी विधानसभा क्षेत्र में संचालित 40 इन्टर कॉलेजों सह उच्च विद्यालयों में अधिकांश बच्चे अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के पढ़ते हैं । लेकिन छात्रावास की व्यवस्था काफी दूर जहानाबाद में है । सरकार से प्रखण्ड मुख्यालय मोदनगंज में पिछड़ी जाति तथा घोसी में अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास की मांग करता हूं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी प्रखंड के बैरबा महादलित टोला को प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्कता प्राप्त नहीं रहने के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अत: सकरपुरा बैरबा के बीच पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर साक्षर भारत मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 'शिक्षा प्रेरकों' की सेवा 31 मार्च, 2018 से ही रद्द कर दी गयी है । सभी शिक्षा प्रेरकों के समायोजन तथा उनके बकाये मानदेय की अविलम्ब भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में पूर्वी चम्पारण के सुगौली प्रखंड के पजियरवा गांव में साम्प्रदायिक साजिश के तहत सैकड़ों भूमिहीन परिवारों के घरों को बुल्डोजर से ध्वस्त करा दिया गया । सभी भूमिहीन परिवारों को पुनर्वासित करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु मजदूरों के सवाल को लेकर मेरा शून्यकाल था लेकिन ये फेक न्यूज के फैक्ट्री के लोग भाग गए । व्हाट्स एप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और पूरे देश में अफवाह चलाते हैं । पिछले दिनों इन्हीं लोगों का गठबंधन था तो ये लोग महाराष्ट्र में बिहारियों पर हमला कर रहे थे और मैंने

कल जो अखबार में पढ़ा उसके आधार पर बनाया था, आज वे लोग भाग गए हैं, मनसे के साथ समझौता करके हमला किए इसलिए मैं अपना जो शून्यकाल है वह न पढ़कर के और इसी को बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष : आप समझ गए हैं कि वह फेक जो है...

श्री अमरजीत कुशवाहा : बिल्कुल फेक है महोदय...

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद, बैठिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : बिल्कुल फेक है और उसका जांच भी आ गया है ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

टर्न-8/सुरज/03.03.2023

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड में मात्र तीन ही पावर सब-स्टेशन हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है।

अतः मैं सरकार से अतिरिक्त पावर सब-स्टेशन निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की बहुप्रचारित मिड-डे-मिल योजना में विद्यालय रसोईयों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है लेकिन वे इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में 53 रुपये में प्रतिदिन खटने को मजबूर हैं, जो न्यूनतम मजदूरी का भी उल्लंघन है । विद्यालय रसोईयों को न्यूनतम मजदूरी देने की मैं मांग करता हूं ।

यहां उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और आठ घंटे वे महिलायें काम करती हैं और उनको पूरे दिन में 53 रुपया मिलता है, उसका जीवनयापन कैसे होगा और ये केन्द्र की सरकार जिसने ये योजना चलाई और उन महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं की बात करते हैं, इस रसोईया में लाखों गरीब महिलायें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये शून्यकाल है ।

श्री सत्यदेव राम : लेकिन उनको 53 रुपया देकर के उसके साथ अन्याय किया जा रहा है । इसलिये मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि आप पूरे सदन के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी का प्रस्ताव...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बहस का ऑवर नहीं है, यह शून्यकाल है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह दुखड़ा है और इस दुखड़े को मैं सदन के सामन रख रहा हूं और यह गरीबों का, दबे-कुचले लोगों का दुखड़ा है ।

अध्यक्ष : अच्छा स्थान अब ग्रहण किया जाय, आपके दुखड़े को सुन लिया गया ।

माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी जो आप माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी को कह रहे थे कि ये शून्यकाल है भाषण देने का समय नहीं है, तो भाषण तो वह दे भी नहीं रहे थे । ये उनका दोष नहीं है, उनकी आवाज का दोष है । महोदय, इसलिये कि कभी जब हम आपके आसन पर रहते थे तो माननीय सदस्य यहां से बोलते थे तो हम बराबर कहते थे कि इनका माइक बंद कर दो, इनको माइक की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जनशिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-1088, दिनांक-19.05.2018 द्वारा सीतामढ़ी जिला तालिमी मरकज के 173 शिक्षा सेवियों को पदमुक्त किया गया था, के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-11447/2018 में पारित आदेश को बहाल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिनांक-20.02.2023 को विभूतिपुर थाना के सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण के पूर्व मुखिया सुरेन्द्र प्रसाद सिंह एवं सत्य नारायण महतो की हत्या दिन-दहाड़े अपराधियों ने कर दी थी ।

मैं सरकार से अपराधियों की गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल चलाने एवं मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग तथा युवा देश के भविष्य हैं । अफसोस होता है तब, जब हमारे इसी देश के भविष्य को धान, गेहूं के खेत में खेलते हुये देखता हूं ।

मैं सरकार से अपेक्षा एवं मांग करता हूं कि पंचायत स्तर पर खेल के मैदान की व्यवस्था की जाय ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के नये परिसर में 12 साल पहले बनकर तैयार ओ0बी0सी0 छात्रावास खंडहर हो गया, शिफ्टिंग के लिये छात्रों के आमरण अनशन के बावजूद अभी तक आवंटित नहीं किया गया । अविलम्ब छात्रावास का जीर्णोद्धार कर छात्रों को आवंटित करने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड के मोरवा उत्तरी पंचायत अन्तर्गत स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा खुदनेश्वर धाम के परिसर में स्थित प्राचीन तालाब की सीढ़ी का निर्माण कार्य अधूरा है ।

अतः जनहित में उपरोक्त तालाब के पूर्ण सीढ़ी निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री मो0 कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अन्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड में निर्मित एस0एच0–103 को विस्तारित करते हुये दर्शन नाला तक सड़क का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलान्तर्गत प्रखंड तरियानी प्रखंड कार्यालयों के छः कमरा का बिना निविदा निकाले भवन तोड़ कर उसका ईंट, दरवाजा, खिड़की बेच दी गयी । इसकी जांच कराते हुये दोषी पदाधिकारियों के वेतन से वसूली की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती रश्मि वर्मा ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के सहार प्रखंड अंतर्गत अवगीला में 02.03.2023 की रात लाल बहादुर पाल और दीनदेयाल पाल की 75 भेडों की मौत कुत्तों के काटने और नाली में गिरने से हो गयी । लोकहित में बाजार भाव से भेंड़ पालकों को पर्याप्त मुआवजा की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री रामबली सिंह यादव, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव जी की ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञापन सं0–01/2019 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग के पत्रांक–636, दिनांक–02.04.2022 से प्रकाशित चयन सूची में कतिपय त्रुटियां परिलक्षित होने के कारण पुनः सुधार कर मेधा सूची प्रकाशित किये जाने हेतु वापस ले लिया गया है । जिसमें सुधार करने की कार्रवाई की जा रही थी कि इसी बीच दिनांक– 19.04.2022 को CWJC No-7312/2021 में माननीय उच्च न्यायालय

द्वारा उक्त प्रकाशित चयन सूची को Set Aside करते हुये निम्न आदेश पारित किया गया:-

" Accordingly, appointments made to extent in terms of Rule 4(A) of Amending Rules, 2017 are set aside and the Bihar State Technical Selection Commission is directed to prepare a fresh select/merit list granting 40% institutional reservation to all the diploma holders, who have obtained their diploma certificate from any polytechnic institutes recognized by AICTU and affiliated by State Board of Technical Institutions Bihar, Patna Within the State of Bihar"

तदोपरांत उक्त न्यायादेश के अनुपालन में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से उक्त न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया । प्राप्त परामर्श के पश्चात् उक्त आदेश के अनुपालन हेतु बिहार राज्य के Private Polytechnic से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दिनांक-01.08.2022 से दिनांक- 11.08.2022 तक काउंसलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया ।

(क्रमश:)

टर्न-9/राहुल/03.03.2023

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (क्रमश:): उक्त के पश्चात् सभी आवश्यक जांच पूर्ण कर मेधासूची प्रकाशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी परन्तु सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-7761/2022 अप्पु कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक-01.12.2022 को विज्ञापन संख्या-01/2019, कनीय अभियंता के परिणाम प्रकाशन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित किया गया है कि Process of selection may carry on, but the result shall not be declared without leave of the court. उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु आयोग द्वारा मेधासूची का प्रकाशन नहीं किया गया । पुन: वर्तमान में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-3411/2022 तथा अन्य सात याचिकाओं में अधियाची विभागों द्वारा दिनांक-25.01.2023 को लिये गये निर्णय में नियुक्ति नियमावली में संशोधन किये जाने का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।

उक्त के आलोक में दिनांक-16.02.2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित निदेश दिया गया है : Ultimately State Government has taken a decision to cancel the process of recruitment to the post of Junior engineer with reference to advertisement issued

on 08.03.2019 and proposed to issue fresh or amendment of rules rectifying certain errors which have crept in existing rules. एवं In light of these new development the state is permitted to carry out necessary amendment and proceed afresh to advertise for of Junior Engineer.

From the date of last advertisement till date, almost four years have elapsed, therefore, such of those candidates who are likely to be over-aged with reference to ensuing advertisement, for such of those candidates (who are applicants to the advertisement dated 08.03.2019), State Government must make a provision in proposed amendment insofar as giving age relaxation as a one time measure. The above exercise shall be completed within a period of four months from the date receipt of this order. उक्त के आलोक में संशोधित मेधासूची का प्रकाशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा नहीं किया गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम सभी जनप्रतिनिधि और सरकार बिहार के युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मुझे यह कहना है कि पहली बात तो है कि इसमें 12-15 वर्षों से संविदा पर कार्यरत अभियंता जो हैं उनकी उम्र काफी हो चली है और फिर से अगर उनको परीक्षा में शामिल कराया जाय तो एक तो उनकी उम्र सीमा पार हो जायेगी और दूसरी बात है कि ये अपने कार्य क्षेत्र में इनका अनुभव काफी है लेकिन किताब से इनका रिश्ता कमजोर हो गया है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये परीक्षा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे । तीसरी बात है कि तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ही डॉक्टर, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, ट्यूटर, कृषि समन्वयक, वेटनरी डॉक्टर आदि की बहाली इसी प्रक्रिया से हुई है जो योगदान करके कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों का यह कहना है कि गलती अगर आयोग ने की है तो सजा इन अभ्यर्थियों को तो नहीं मिलनी चाहिए और इसीलिए मुझे कहना है कि लगभग पूरे बिहार में ढ़ाई हजार के आस-पास की संख्या में 12-15 वर्षों से कार्यरत अभियंता हैं तो क्या उन्हें योगदान नहीं कराया जा सकता है चूंकि यह उनके जीवन का सवाल है, उम्र समाप्त हो जायेगी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने हाईकोर्ट के सारे निर्णयों को बता दिया तो उसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है । हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा उसमें उम्र का भी रिलेक्शेसन दिया जायेगा । वर्ष 2019 में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उस डेट से उनकी उम्र को बढ़ाने का भी उसमें प्रोविजन रहेगा यह मैंने पढ़ दिया तो उससे अधिक और क्या कह सकता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इनका नाम नहीं है तो ये कैसे पूरक कर सकते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ का नाम है ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहना था कि मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि बी0टी0एस0सी0 ने माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे, जो गाईडलाईन थी उसका पालन नहीं किया और पालन न करके बी0टी0एस0सी0 ने अंक आधारित, परीक्षा इसमें नहीं थी ये अंक आधारित एक मेधा सूची तैयार करके लोगों को उसमें किया गया और बड़े पैमाने पर उसमें फर्जी डिग्री भी शामिल हुई...

अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री पर आइये ।

श्री संदीप सौरभ : 417 एफ0आई0आर0 16 फरवरी को उसमें दर्ज की गई हैं कई अभ्यर्थियों पर जिनकी डिग्री फर्जी थी । हम यह जानना चाहते हैं और इसी तरह के कई और मामले जैसे सरकार का कहना है कि बी0टी0एस0सी0 हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बी0पी0एस0सी0 हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो । ये तमाम आयोग जो हैं ये सरकार से स्वायत्त हैं तो सरकार से स्वायत्त हैं इस नाम पर एक तो किसी माननीय सदस्यों के लेटर का वहां से ठीक से रिस्पोन्स नहीं आता है । उनका मानना है कि वे स्वायत्त हैं और दूसरी बात की जो गलतियां हुई जैसे गाईडलाईन रहने के बावजूद अंक आधारित आपने किया, एफ0आई0आर0 तो बाद में हुई । इसके अलावा जब यह एफ0आई0आर0 का मामला सामने आया और रिजल्ट को विदड्रॉ किया गया उसके बाद बी0टी0एस0सी0 की तरफ से कहा गया कि इसमें एक जांच कमेटी बना देते हैं और वह जांच करेगी फर्जी सर्टिफिकेट की लेकिन दुर्भाग्यवश यह हुआ उसमें कि जहां-जहां से कमेटी गई कमेटी के जाने से पहले कमेटी के सदस्य जो जांच करने वाले हैं उनका नाम और उनका मोबाईल नंबर पब्लिक में आ गया और वह कमेटी कहीं गई भी नहीं तो इसलिए बड़े पैमाने पर धांधली होती रही । पहले शुरुआत में आयोग ने कुछ नाम को विदड्रॉ किया, फिर बाद में पूरा रिजल्ट विदड्रॉ किया । हम इसमें यह मांग करते हैं कि वह चाहे बी0टी0एस0सी0 हो या इस तरह की और बहालियां हों, सरकार जो जवाबदेह पदाधिकारी उसमें हैं, जो शीर्ष पदों पर आयोग में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ अगर कोई गलती साबित होती है तब कार्रवाई करने का विचार रखती है कि नहीं रखती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मामला न्यायालय में है, न्यायालय का निर्णय आयेगा उसको देखा जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय न्यायालय के भिन्न-भिन्न तिथियों पर जो फैसले हुए सबकी जानकारी माननीय मंत्री जी ने दी । माननीय मंत्री जी का कहना है कि अब जो फैसले आयेंगे उसके आलोक में कार्रवाई होगी इसलिए मैं अब माननीय...

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय,...

श्री संदीप सौरभ : महोदय, अगर सिर्फ माननीय कोर्ट के आधार पर ही विभाग पर कार्रवाई होगी तो ये तमाम जो आयोग हैं ये सामान्य प्रशासन विभाग, जिनके मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं उसके मातहत क्यों आता है । सामान्य प्रशासन विभाग के मातहत अगर ये सारे आयोग हैं तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि ये आयोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात कि सरकार इस तरह का नियम क्यों नहीं बनाती है कि इन आयोगों में जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हुए हैं उसमें तीन साल से ज्यादा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने जो उत्तर पढ़ा उसको ठीक से माननीय सदस्य ने सुना नहीं है । तकनीकी आयोग ने कार्रवाई प्रक्रिया पूरी की, उसमें कुछ शिकायत आई इसीलिए तो उसको रोककर के त्रुटियों को सुधार करने का काम किया गया । इसी बीच लोग हाई कोर्ट चले गये और जो कोर्ट का निर्णय आया उस सबको मैंने पढ़ दिया तो कहां कोई उसमें गुंजाइश है कि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पूरी जानकारी लेकर के तब बोलना चाहिए ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, 200 से ज्यादा एफ0आई0आर0 सिर्फ बी0टी0एस0सी0 जेई परीक्षा में कोर्ट में केस चल रहा है । आयोग एक बहाली लेकर के आता है और उसमें 200 से ज्यादा केस हो जा रहे हैं तो कितने लूप्होल उसकी विज्ञप्ति निकालने में किये गये हैं आयोग की तरफ से तो क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वे अलग से प्रश्न करें इस संबंध में ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार पहले आप अपनी सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री अजय कुमार, भाई वीरेन्द्र एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक गांवों एवं शहरों की आबादी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है लेकिन बढ़ती आबादी के अनुपात से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होने के कारण घटना सहित राज्य के 19 जिलों में वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है । बिहार के कई शहर वायु प्रदूषण के मामले में अव्वल रहे हैं, जबकि

बिहार के शहरों में इंडस्ट्री की संख्या बहुत ही कम है, फिर भी यह देश में सबसे अधिक प्रदूषित राज्य है । राज्य के कुछ शहरों का ए0क्यू0आई0 लेवल पटना–424, मुजफ्फरपुर–455, समस्तीपुर–459, पूर्णिया–446, कटिहार–449, भागलपुर–477, दरभंगा–447, बेगूसराय–470, सीवान–488, मुंगेर–378, आरा–372, वैशाली–371, अररिया–357, किशनगंज–353, गया–349, मोतिहारी–343, औरंगाबाद–323, छपरा–420, सहरसा–405 है । प्रदूषण की वजह से राज्य के लोग प्रभावित हो रहे हैं ।

अतः राज्य को प्रदूषण से निजात दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : श्री राकेश कुमार रौशन अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री राकेश कुमार रौशन, रामबली सिंह यादव एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने बहुत सारे शहरी इलाकों को ग्राम पंचायत से हटाकर नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम में स्थानांतरित किया है, लेकिन नवगठित शहरी निकायों में बहुत जगहों पर कार्यपालक पदाधिकारी का पद रिक्त है, जिसके चलते विकास की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है । कुछ जगहों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं मिलने के कारण विकास का कार्य नहीं हो रहा है ।

अतः जनहित में बिहार राज्य अंतर्गत नवगठित शहरी निकायों में अविलंब कार्यपालक पदाधिकारी पदस्थापित करने एवं जहां–जहां प्रभार में पदाधिकारी हैं उन्हें वित्तीय अधिकार देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री अजय बाबू और रौशन जी, दोनों ने अपने ध्यानाकर्षण को पढ़ा है चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए आज के दोनों ध्यानाकर्षण अगली तिथि को भी रहेंगे, उत्तर अगली तिथि को दिया जायेगा ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/मुकुल/03.03.2023

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''आज दिनांक- 03 मार्च, 2023 की कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''आज दिनांक-03 मार्च, 2023 की कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :

1. शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2023 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो,

2. शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2023 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जल संसाधन विभाग से संबंधित आय-व्ययक के अनुदान की मांग शुक्रवार, दिनांक-24 मार्च, 2023 को गृह विभाग से संबंधित आय-व्ययक के अनुदान की मांग के पश्चात मुखबंद (गिलोटीन) के माध्यम से निष्पादित किए जाएं :

3- शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2023 के सभी स्वीकृत प्रश्नों को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिये जाएं,

4- शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह कैसा बहुमत है । यह पर्व हिन्दू धर्म का है । महोदय, प्रेस मीडिया भी 07 मार्च, 2023 को बंद रहेगा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर दिनांक-02 मार्च, 2023 से जारी सामान्य विमर्श अब प्रारंभ होगा । माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा अपना पक्ष रखें । आपका समय 15 मिनट का है । माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्यों शुक्रवार को बंद हुआ, हमने वहां पर भी प्रतिकार किया है ।

अध्यक्ष : कार्य मंत्रणा समिति ने जो निर्णय लिया है वह सर्वमान्य है ।

माननीय सदस्य, आप अपना भाषण शुरू करें । श्री नीतीश मिश्रा जी, आप अपना भाषण शुरू करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है, जब प्रेस मीडिया उस दिन बंद रहेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा जी आपका समय जा रहा है, आप बोलिए ।

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझको सरकार द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया । साथ ही, अपने विधायक दल के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको यह बोलने का अवसर दिया । माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया और लगातार जो सदन में उनको देखते हैं तो बहुत पुरानी बातें भी याद आती हैं कि मुझको जब से अपना बचपन याद है, तब से मैं उनको देख रहा हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट पर मैं अपनी कुछ प्रतिक्रिया रखूं, कुछ समय मैं असमंजस में भी था लेकिन जब हम सदन में आते हैं तो सभी सदस्य एक समान होते हैं और मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के नाते, एक बिहारी होने के नाते, बजट को जो मैंने अपनी समझ से समझा है बिना उसकी राजनीति में गये हुए, मैं उन विषयों को रखना चाहूंगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट संबोधन में इथेनॉल का जिक्र किया और यही सदन है जहां पर मैं पहली बार जब निर्वाचित होकर आया, पहली बार आया तो हमलोग तो अभूतपूर्व विधायक थे विधान सभा भंग कर दिया गया था । लेकिन जब दूसरी बार वर्ष 2005 में जीतकर आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको गन्ना विकास विभाग दिया था और मुझे अपने साथ जो न्याय के साथ विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी उसमें अपना साथी बनाया था और मुझको उन्होंने चुनौती दी थी कि बिहार की जितनी बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, चीनी मिलों को चालू कराना है । मुझको प्रसन्नता है कि वर्ष 2006 में ही जो 15 चीनी मिलें बंद थीं उनमें से इथेनॉल की इकाइयां भी प्रारंभ हुईं, बिहार में पहली बार गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ, चीनी मिलों से अपना बिजली उत्पादन भी, क्योंकि वर्ष 2005-06 में आपको स्मरण होगा कि बिहार की अपनी जनरेशन नहीं हुआ करती थी बिजली में तो चीनी मिलों के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ और यही सदन है जहां पर शुगर केन परचेज और रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने के लिए बिहार विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा था । उस समय बिहार को लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था लेकिन उस समय सरकार की जो नीति थी वह बिहार को अनुमति नहीं दे पा रही थी कि बिहार उसमें आगे बढ़े

और कतिपय कारणों से वह जो निवेश था वह निवेश फिर रुक गया । मुझको अभी भी याद है दिनांक–31 मार्च, 2008 को एन0डी0ए0 विधायक दल की बैठक थी और दो बंद पड़ी चीनी मिलें पश्चिम चम्पारण की लौरिया और पूर्वी चम्पारण की सुगौली, जिन्हें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने लिया है । उसके शुरुआती प्रोसेस के बाद उसका जो चेक आया था, उसे मैं प्रसन्नता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर दिखाया कि जो टास्क आपने बंद चीनी मिलों का मुझे दिया था उनमें दो प्रारंभ हुआ है, शेष भी होगा । लेकिन नहीं मालूम क्या हुआ, 13 दिन बाद ही सभी मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया और बहुत सारे मैम्बर अभी भी हैं जो उस समय के मंत्रिमंडल में थे । लेकिन यह मेरी भी समझ के बाहर था कि ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि सभी मंत्री जो उस समय कार्य कर रहे थे, सभी का विभाग बदला गया और अब तो नये मंत्री बनते हैं, सीधे कैबिनेट मंत्री बनते हैं, हमलोग राज्य मंत्री बने थे लेकिन राज्य मंत्री के साथ स्वतंत्र प्रभार मिला था तो कहीं न कहीं बिहार में निवेश की जो प्रक्रिया थी वह रुकती चली गई । मैंने इसलिए इस बात का संदर्भ किया, क्योंकि जब हम बिहार की विकास दर की बात करते हैं, ग्रोथ रेट की बात करते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि बिहार ने लगातार एक अच्छी विकास दल को मेंटेन रखा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिसका मैं संदर्भ आगे रखूंगा, उस पर मैं कुछ आगे आपको कहूंगा । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें चार बिंदुओं को उन्होंने रेखांकित किया है । राजकोषीय घाटा को 3 प्रतिशत की सीमा के अंदर रखना जो सरकार की अनिवार्यता है, केन्द्र सरकार के कानून के तहत, राजस्व घाटा को समाप्त करना और राजस्व अधिशेष जो रेवेन्यू सरप्लस है उसको जुटाना और कुल बकाया राशि हमारा जो ऋण होता है या जो हम इंट्रेस्ट पे करते हैं, हमारा अपना जनरेशन कैसे बढ़े कि हमारी उस पर जो निर्भरता है वह घटे और हमलोग वर्ष 2023–24 में अधिक विकास दर को प्राप्त करें । बहुत बातें आ गई हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम यह नहीं कहेंगे कि बजट का आकार क्या है, उसमें केन्द्र सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन क्या है, बिहार के टैक्सेज का शेयर कितना है, बिहार की बॉरोइंग कितनी है या बिहार कितना ऋण लेता है । मैं उन सब आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वह टाइम टेकिंग है । कुछ बातें जो बजट में मेरे सामने आईं, अब हमलोग चौथे कृषि रोडमैप की ओर जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही किसानों का एक समागम हुआ था और चौथे कृषि रोडमैप की तैयारी में हमलोग लगे थे । कृषि रोडमैप ने कितना सक्सेस पाया, क्या परफॉर्मेंस रहा मैं उसके डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा । लेकिन जब हम इसी वर्ष का बजट एलोकेशन

देख रहे थे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन क्या है तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी वह बहुत कम है और लेसदेन 3 परसेंट है तो कहीं न मुझको यह लगता है जब हम किसानों और कृषि की बात करते हैं, हम जब कृषि रोडमैप की ओर जा रहे हैं तब हमारी इस एलोकेशन से क्या होगा । रोजगार पर बहुत बल दिया गया और मुझको लगता है कि आने वाले समय में स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है रोजगार सृजन में । हमने उद्योग विभाग का बजट देखा तो 1 प्रतिशत का उनका एलोकेशन है तो हम नहीं समझ सकते हैं कि अगर आप दूरगामी विकास दर की बात करते हैं और उसको सस्टेन करना है तो आप कैसे जायेंगे । हमारी जो भी राशि है उसमें अधिकांश राशि हमारी रि-पेमेंट में जाती है तो हम एक्चुअल अपना जो एक्सपेंस करते हैं, चाहे डेवल्पमेंट स्कीम्स पर, प्लान स्कीम्स पर उसके लिए हमारी राशि कम होती है क्योंकि मेजर पार्ट हमारे बजट का जो हमारा डेट है, जो इंट्रेस्ट है उसके रि-पेमेंट में जाता है । मुझको आर0बी0आई0 का एक डाटा दिखा और आर0बी0आई0 का एक रिस्क एनालाइसिस है जो आर0बी0आई0 बुलेटिन 16 जून, 2022 का है, माननीय मंत्री जी भी इससे अवगत होंगे, कुछ राज्यों को हाइली स्ट्रेस मतलब जो डेट वाले रिस्क जोन में आर0बी0आई0 ने चिन्हित किया है उसमें बिहार भी है । मैं सिर्फ इसलिए इन बातों को संज्ञान में ला रहा हूं कि सब चाहता है बिहार आगे बढ़े ।

क्रमशः

टर्न-11/यानपति/03.03.2023

(क्रमशः)

श्री नीतीश मिश्राः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इन विषयों को सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं कि इन विषयों को हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा राज्य, हमारी डिपेन्डेन्सी अगर बहुत बढ़ती जाएगी बौरोइंग्स, पर हमारी उतनी अर्निंग नहीं है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन नहीं है तो कहीं न कहीं हमको यह नुकसान होगा । एफ0आर0बी0एम0 का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया लगातार 2005 से एक बेहतर फिजिकल मैनेजमेंट की ओर हैं हमलोग । 2005 में जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो बिहार की जो कैपेसिटी थी जो उस समय का बजट आकार था और आज के बजट आकार की आप तुलना करेंगे बिहार ने अपने संसाधनों को, अपने सिस्टम को बेहतर बनाया, अब उस बेहतर बनने का परिणाम है कि आज हमारा बजट साइज 2 लाख 60 हजार करोड़ से भी अधिक की ओर जा रहा है तो बुनियाद उस समय रखी गयी । साथ ही एक

हमको बड़ा विस्मय भी लगता है कि ग्रोथ तो हमारा हो रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है वह क्यों नहीं बढ़ पा रहा है । मतलब बिहार इज ग्रोइंग बट बिहारी इज नोट ग्रोइंग । यह क्या एक विडंबना है या यह क्या प्रश्न है । हम अभी का देख रहे थे कि राष्ट्रीय औसत अगर प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख के आसपास है, 1 लाख 97 हजार, बिहार का लगभग 50 हजार के आसपास आता है वहीं हम अपने मिथिला क्षेत्र क्योंकि उधर से हम आते हैं तो हमने मधुबनी का देखा तो मेरी जिज्ञासा हुई कि हम जब नेशनल एवरेज कंपेयर करते हैं, बिहार की तुलना करते हैं तो हमारे मिथिला क्षेत्र का क्या है तो मधुबनी का 22600 है और सबसे कम हमारा सीमांचल का है, अररिया का है बिहार का लोवेस्ट है वह । तो यह हम कहीं न कहीं विकास दर की तो बात कर रहे हैं, विकास दर हम मेन्टेन कर रहे हैं लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम हमारी प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ पा रही है यह कहीं न कहीं हमारे लिए चिंता वाली बात जरूर है । हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारा वर्किंग पॉपुलेशन भी उस तुलना में कम है अगर राष्ट्रीय औसत आप देखेंगे जो 55 के आसपास है बिहार में अगर मेल-फीमेल हमलोग मिला लेते हैं तो 40 प्रतिशत है तो कहीं न कहीं जो हमारा वर्कफोर्स है, उसकी जो सहभागिता है उनको अगर हम मेन स्ट्रीम में नहीं ला पा रहे हैं वकफोर्स का हमारा जो कैपेसिटी है वह हमारा नहीं बढ़ रहा है । आज हमने एक डाटा देखा, रोजगार पर बहुत जोर दिया गया यह फरवरी 2023 का सी0एम0आई0 का रिपोर्ट है जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी है कि बिहार का जो अनएंप्लोयमेंट रेट है अभी 12.3 है और इंडिया का 7.5 है । तो यह कहीं न कहीं जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप बेटर ऑपोरच्युनिटी दे रहे हैं, बजट भाषण में बहुत ज्यादा रोजगार पर था फोकस तो उसमें एक-दो बातें हमलोग रखना चाहेंगे एक जब आप रोजगार की बात करते हैं तो बड़े साइज को आपलोग भूल रहे हैं जो हमारे यहां कंट्रेक्ट पर या आउटसोर्स पर हमारे ही बिहार के लोग काम कर रहे हैं । विभिन्न विभागों में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, उनको सरकार क्या पैसा दे रही है, एक्चुअल पेमेंट उनको क्या हो रहा है तो हमारे यहां कहीं न कहीं वैकेंसी है तभी हम उनसे काम ले रहे हैं । तो अगर हमारे पास वैकेंसी है तो हम उसको क्यों नहीं ऑब्जर्ब करने की बात करते हैं और वह एक बहुत बड़ा समूह है, दूसरा जब हम अपने यहां अगर हम एक हमने देखा 2015 का सुशासन का कार्यक्रम है जब नई सरकार 2015 में बनी थी तो उसमें 20 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं जो अनएम्प्लोयड हैं उनको 1000 रुपया प्रतिमाह देने का उसमें तय किया गया था कि उनको दो वर्षों तक वह दिया जाएगा जबतक उनको रोजगार

नहीं मिलता । यह आंकड़ा मैंने फिर ढूंढ़ना चाहा कि इसमें कितनी प्रगति हुई, कितने यूथ को दिया गया लेकिन नहीं मिला तो मेरी चिंता यही है कि आप सरकारी निवेश से या आप सिर्फ गवर्नमेंट में जो हमारी गवर्नमेंट की कैपेसिटी है जॉब्स की वह उतनी कभी नहीं हो सकती है कि बिहार के सभी युवाओं को दें तो हमारे पास अल्टिमेटिव क्या है, क्योंकि इनके बजट भाषण में सेल्फ एम्प्लोयमेंट पर भी जोर था कि स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे तो हम स्टार्टअप क्योंकि पूरे विश्व में स्टार्टअप एक बहुत बेहतर विकल्प के रूप में आ रहा है तो मेरी दृष्टि स्टार्टअप पर गई और आज हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व में भारत जो स्टार्टअप इको सिस्टम है उसमें तीसरे स्थान पर है और यह सब हमारे देश के युवाओं की ही देन है । अब उसमें लगभग 136 बिलियन यू0एस0 डॉलर का आज हमारा इको सिस्टम बना हुआ है स्टार्टअप का और देश में लगभग 92 हजार स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं लेकिन बिहार में 300-400 हम उस ढंग से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो युवाओं को जब तक हम स्वरोजगार की ओर या अपनी स्कीम्स हैं इनकी स्टार्टअप को हेल्प करते हैं लेकिन फिर भी अगर नेशनल लेवल पर हम देखें तो जिस अनुपात में हमको बढ़ना चाहिए हम नहीं बढ़ पा रहे हैं । फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट अध्यक्ष महोदय, हम 90 के दशक में नहीं जाना चाहेंगे कि जब आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ तो बिहार उससे वंचित रहा । जिन भी कारणों से वह वंचित रहा बिहार, अब तो वह समय नहीं लौटेगा आज पुनः एक अवसर है जब देश में एफ0डी0आई0 बहुत वृहत पैमाने पर आ रहा है, एक आंकड़ा हम देख रहे थे इन्वेस्ट इंडिया का कि अभीतक भारत में 950 बिलियन यू0एस0 डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट हुआ है जिस में पिछले दो वर्षों में 532 बिलियन यू0एस0 डॉलर आया है और यह 160 से अधिक देशों से आया है तो कहीं न कहीं जो भारत की स्वीकार्यता है वह बरती जा रही है और लोग इच्छुक हो रहे हैं कि हम भारत में निवेश करें और यही नहीं लॉकडाउन जब संपूर्ण विश्व लॉकडाउन को झेल रहा था उस समय भी लगभग 83.5 बिलियन यू0एस0 डॉलर हमारा फॉरेन निवेश आया था, अब समय कम है अध्यक्ष महोदय मैं दो-तीन चीजें सिर्फ सरकार के ध्यान में, माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, एक लंबा समय मेरा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बीता है और मैं जो विषय रखना चाहता हूं मैं संशय में भी था कि मैं यह बोलूं या नहीं बोलूं लेकिन मुझको लगता है जो मैंने अनुभव किया है उन बातों को जरूर रखें और माननीय मंत्री जी ने जो हमारा कास्ट सर्वे हो रहा है उसका उल्लेख किया कि 500 करोड़ का एलोकेशन है बहुत सारे सदस्य जो 2010 से 2015 के बीच में सदन में रहे होंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हमलोगों ने किया था और बहुत बड़े पैमाने

पर पूरे देश में उसका सर्वेक्षण हुआ था और हमलोगों ने भी किया, वह बहुत ही साइंटिफिक तरीके से था मुझको नहीं जानकारी है इसलिए मैं यह भी मानता हूं कि मेरे पास किस ढंग से हो रहा है उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है मैंने बहुत सर्च किया पर वह नहीं मिला । 78 वीडियो कंफेरेंसिंग हमलोगों ने किया था 22 फुल पेज विज्ञापन हमने निकाला था लोगों को जानकारी देने के लिए और 12 ईमेल, मैंने सर्च किया 12 ईमेल हमने माननीय विधान मंडल के सदस्यों को भेजा था कि आप देख लीजिए कैसे-कैसे होगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका मात्र दो मिनट है ।

श्री नीतीश मिश्रा: बस दो ही मिनट लेंगे अध्यक्ष महोदय, उसमें प्रॉब्लम यह आई कि जब हमलोगों ने ऑब्जेक्शंस मांगा, जब डाटा रिलीज करने से पहले सरकार का, भारत सरकार का निर्णय था कि सार्वजनिक स्थान पर ही देना है लेकिन माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि प्रत्येक हाउस होल्ड में उस डाटा को दीजिए ताकि लोगों को अगर कोई शिकायत है तो उसको वह दूर कर सकें । तो जो उनका एक कॉज एक एप्लीकेशन था क्लेम ऑब्जेक्शन पैकिंग सिस्टम एक करोड़ आपत्तियां हमलोगों को प्राप्त हुई और जब एक करोड़ आपत्तियां प्राप्त हुई उसको हमलोगों ने आकलन किया तो 50 लाख आपत्तियों को हमलोगों ने सही माना यानी कहीं न कहीं त्रुटि हुई थी । मैं सिर्फ इस विषय को लाना चाह रहा हूं कि आप जिस भी ढंग से इस प्रोसेस को कर रहे हों कहीं न कहीं आप यह ऑपोरच्युनिटी जरूर दीजिए लोगों को कि अगर डाटा रिलीज करने से पहले जो एक्चुअल आ रहा है वह सही में जो ग्राउंड पर है वह वास्तविकता है या नहीं है क्योंकि यह एक संवेदनशील विषय है इसलिए मैं आपके ध्यान में इस विषय को लाना चाह रहा था और एक अंतिम बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री, हमने देखा 2015 का कार्यक्रम, 2010 का कार्यक्रम, 2020 का कार्यक्रम जो सुशासन का होता है और उसकी मॉनिटरिंग की, निगरानी का जिम्मा प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है यहां बहुत सारे प्रभारी मंत्री बैठे होंगे, मेरे संज्ञान में नहीं है कि कब आपको जिला प्रशासन ने डिफरेंट स्कीम के बारे में आपको ऑथराइज किया और कब आपलोगों ने जिलों में इस ढंग की बैठक की । उन सारे पुराने सर्कुलर्स को हमने देखा । एक विषय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हैं 2014 में एक नया काडर बना बी0डी0ओ0 का उनको तीन साल के लिए प्रभार दिया गया, एक लंबा समय बीत गया उनको फिर बी0डी0ओ0 में एप्वाइंटमेंट करना था, 8 वर्ष बीत गए हैं नहीं हुआ । मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सुशासन की जब हम बात करते हैं तो उसका रियल रिफ्लेक्शन थाना और ब्लॉक से आता है, अगर थाना और ब्लॉक हमारा बेहतर तरीके से

संचालित हो रहा है तभी लोगों के पास सही मायने में हम गुड गवर्नेंस को पहुंचा पाते हैं तो इन विषयों को जरूर देखना चाहिए और एक विषय.....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री नीतीश मिश्रा: 30 सेकेंड अध्यक्ष महोदय, एक विषय, क्योंकि सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवा के प्रति चिंतित रहते हैं जो हमारी एंबुलेंस सेवा चल रही है, यह विषय माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं 2016 से जो 102 एंबुलेंस हैं वह संचालित हैं और 5 वर्षों बाद नई निविदा निकाली गई, जानकारी एक मुझको मिली है, माननीय वित्त मंत्री जी उसको कंफर्म करेंगे कि 2016 का जो दर तय था एजेंसी के साथ, किस एजेंसी को मिला, क्या मिला मैं उसमें नहीं जा रहा हूं लेकिन मेरी जानकारी में 21 परसेंट बिलो मतलब 2016 का जो रेट था, 2022 में 21 प्रतिशत कम के रेट पर उनको सेवा देने के लिए एग्रीमेंट किया गया तो यह मुझको लगता है कि यह कैसे व्यावहारिक होगा, आप गुणवत्ता को कैसे मेन्टेन करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन दर बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट की स्टेचुरिटरी रिक्वायरमेंट्स प्रोविडेंट फंड और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इस विषय को जरूर देखना चाहेंगे कि कहीं न कहीं गरीबों को जो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएगी उसमें कहीं कमी नहीं रहे । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, मैंने सिर्फ कुछ विषयों को सरकार के संज्ञान में लाना चाहा है कि अगर सरकार उसपर अमल करेगी तो हमारे बिहारियों का भला होगा और कितना हमलोग सहेंगे अध्यक्ष महोदय, अब बिहार भी आगे बढ़ना चाहता है और बिहार के युवा भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार अपना पक्ष रखें । समय 10 मिनट ।

टर्न-12/अंजली/03.03.2023

श्री सतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्रीजी और उप मुख्यमंत्रीजी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बजट के पक्ष में हमको बोलने का मौका मिला और हमारी बजट ऐसे समय में आई है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी और उप मुख्यमंत्रीजी के लिए एक ही बात कहेंगे कि माना कि देश में अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है, तो ये दिया जलाने का काम जो हमारी सरकार ने किया है, इस दिये से पूरे देश को रौशनी मिलेगी और जब हमारे बिहार की बात होती है तो महिला सशक्तिकरण बिहार की एक पहचान रही है महोदय, जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी और जो 35 प्रतिशत सिपाही में हमारी महिलाएं दिखती हैं ये बिहार का प्रतीक आज बन गई हैं जिसकी

चर्चा पूरे देश में हो रही है । महिला प्रतीक के रूप में पूरे देश में पहली महिला को हम सम्मान करते हुए राष्ट्र माता भारत की पहली शिक्षिका सावित्री बाई फुले की याद आती है, जिनकी कल्पना थी कि जब तक महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तब तक देश विकास नहीं कर सकता है और जब सावित्री बाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकली थीं तो इस देश के मनुवादिओं ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था यह पूरी दुनिया जानती है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और बिहार का बजट एक अनोखा बजट है जिसमें अनुसूचित जाति की बालिकाएं यदि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करती हैं तो उनको दस हजार रुपया पोषाहार राशि मिलेगी, द्वितीय श्रेणी से पास करती हैं तो आठ हजार रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगी और अगर इंटर पास करती हैं तो पच्चीस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है और यदि वे ग्रेजुएशन कर जाती हैं तो पच्चास हजार रुपया उनको प्रोत्साहन राशि आगे पढ़ाई के लिए मिलती है तो ये हम जानते हैं कि यह सावित्री बाई फुले के सपने को पूरा करने वाला बजट है । हम कहना चाहते हैं कि आज इसी देश में महिलाओं को अधम कहा गया, इसी देश में महिलाओं को ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी कह कर के संबोधित किया गया लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं के हाथ में बंदूक थमाकर के यह साबित कर दिया कि महिलाएं अबला नहीं हैं, महिलाएं ताड़ना की अधिकारी नहीं हैं, महिलाओं को भी समान अधिकार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, जो लोग महिलाओं को गुलाम बनाकर के रखना चाहते हैं उनको पीड़ा होगी । महोदय, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की एक कल्पना है कि महिलाएं आगे बढ़ें और इस बात को हम देखते हैं कि प्रथम से आठवीं क्लास के बच्चों के जो एडमिशन हुए हैं उसमें 1 करोड़ 9 लाख अगर छात्रों का एडमिशन हुआ है तो 1 करोड़ 5 लाख छात्राओं का भी एडमिशन हुआ है इसका मतलब है कि हरेक परिवार अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहता है ऐसे ही हमारी सावित्री बाई फुले के सपने को साकार किया जा सकता है । महोदय, इसलिए हम आगे कहना चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के तहत लगभग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात जारी रखिए ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हमलोग जब तिरंगा फहराते थे तो भारत माता की जय लगाते थे लेकिन उसके आगे भी हमलोग लगाते थे कि भारत मां के चार सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हमारे साथी लोग भूल गए हैं तो वही भारत माता, वही सावित्री बाई फुले, वही डॉक्टर अम्बेडकर की माता, वही जो सबरी थी, वही भारत माता जो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम करने वाली, जीतन राम मांझी के साथ काम करने वाली या वही भारत माता जो आपने देखा है कि हाथरस की यौन पीड़ित की मां आज भी अस्थि क्लश अपने हाथ में लेकर के घूम रही हैं या वह बिलकिस बानो जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनके साथ-साथ उनकी परिवार की भी हत्या कर दी गई लेकिन कुछ साथी उनके सम्मान के लिए जब वे जेल से छूटते हैं तो माला और मिठाई बांटने का काम करते हैं । क्या वह भारत माता की तस्वीर नहीं है ? तो यह साफ-साफ दर्शाता है कि ये भारत माता का भी चीरहरण करना चाहते हैं उसको भी तोड़-मरोड़ करके बांटना चाहते हैं, भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं, जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं लेकिन हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उस भारत माता की कल्पना को ये सचमुच में साकार कर रहे हैं और यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या हो बौध भाई सब के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और सब के विकास का ध्यान रखा गया है । अल्पसंख्यकों के विकास पर जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आज बिहार में अल्पसंख्यक छात्रावास सही तरीके से संचालित हो रहे हैं, बालिकाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया गया है उसमें भोजन की व्यवस्था की गई है, पढ़ाई की व्यवस्था की गई है और उनके भी बच्चे जब छात्रावास में रहते हैं उनकी भी पढ़ाई में मदद के लिए एक हजार रुपया प्रति माह और 14 किलो अनाज हमारी सरकार उनको भी दे रही है महोदय, यह है न्याय के साथ विकास वाली बजट और बजट में अनुसूचित जाति की बात न हो, स्वास्थ्य विभाग की बात न हो, स्वास्थ्य विभाग में जो आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने निर्णय लिया है यह पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायकों के अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, इससे हम विधायकों का सम्मान बढ़ा है । हम जनता के बीच में कहते हैं कि हमारी अनुशंसा पर आपके यहां अस्पताल बना है, यह इससे पहले नहीं होता था तो कुछ अधिकारी और मंत्री बैठकर के तय कर लेते थे लेकिन हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाने का श्री तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है और 122

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1379 स्वास्थ्य संस्थाएं पूरे राज्य में बन रहे हैं जिस पर 1754 करोड़ रुपया खर्चा किया जायेगा तो बिहार ने पिछले कोरोना की जो त्रासदी देखी थी उस त्रासदी को देखते हुए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बजट बनाया है उससे सबको लाभ मिलेगा । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अनुसूचित जाति और बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन जब बिहार में अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति की बात होती है तो उसमें भी कहते हैं कि आपको 40 प्रतिशत राज्य का पैसा मिलाना पड़ेगा, ये कैसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति का विकास कराना चाहते हैं ? जबकि पहले अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति के मद में शत प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार का होता था तो ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़े नहीं, इसलिए इन्होंने 40 और 60 का रेशियो तय किया महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि आदरणीय आप तमाम सम्मानीय सदस्यगण, प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जब तक अनुसूचित जाति के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है और विश्व गुरु तो बनने से रह गया भैया तो इसलिए बिहार को शत प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति में केंद्र को पैसा भेजना चाहिए जैसे अपने राज्यों में भेजने का काम करते हैं उसी तरीके से बिहार को भी भेजने का काम करना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मात्र दो मिनट समय शेष है ।

श्री सतीश कुमार : धन्यवाद महोदय । दूसरा महोदय, आज बिहार के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज गंगाजल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम की विश्व में चर्चा हो रही है। आज उसको राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित सीबीआईपी अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया जा रहा है । बिहार का गौरव बढ़ाने वाली महागठबंधन की सरकार, जिसके नेतृत्व कर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिसके नेतृत्व कर्ता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो कर रहे हैं इससे आम आवाम गरीबों का सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है और उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव व छेड़छाड़ न हो इसके लिए बिहार में 112 नंबर डायल की एक सुविधा स्थापित की है, यदि किसी भी संकट में आप 112 नंबर डायल करते हैं तो पंद्रह से बीस मिनट के अंदर मदद वाली गाड़ी आपकी पहुंच जाएगी और आपको मदद पहुंचाने का काम किया जायेगा । इसलिए दूसरा हम एक और बात सरकार से आग्रह करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, बीस सेकेंड में हम अपनी बात को खत्म करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, इस देश को एक सपना दिखाया गया कि हवाई चप्पल वाले, हवाई जहाज पर चढ़ेंगे लेकिन हमने देखा है कोरोना काल में कि उनका हवाई चप्पल भी छीन ली गई है । इस देश को एक सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आयेंगे लेकिन कैसे अच्छे दिन आयेंगे जब पंद्रह सौ रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा तो उनके घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा तो अच्छे दिन कैसे आयेंगे ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एक सेकेंड बस । जब हम गांव में गए थे तो एक महिला ने जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, उसने एक बात कही है कि ऐ बाबू ये देखिए मोदी का खेल कि 240 करूआ तेल, इस पर क्यों नहीं विधान सभा में बोलते हैं । यह क्यों नहीं बोलते हैं कि अडानी और मोदी में मेल हुआ और 110 रुपया पेट्रोल हुआ तो क्यों नहीं जाकर बोलते हैं तो यह गांव-गिरांव में लोग बोल रहे हैं, महंगाई से त्रस्त हैं । आप भी जनता से चुनकर आते हैं, आपसे भी निवेदन है कि बाहर जब प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो तो पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर का दाम जो बढ़ा है उसका भी विरोध कीजिए नहीं तो जनता आने वाले दिनों में आपको माफ नहीं करेगी ।

टर्न-13/सत्येन्द्र/03.03.2023

अध्यक्ष: अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीश कुमार: किसानों को जो खाद मिलता था पहले महोदय, वह 50 किलो का बोरा आता था लेकिन आज वह 45 किलो कर दिया गया है। इस प्रकार 5 किलो जो डंडी मारने का आपलोगों ने काम किया है यह कतई उचित नहीं है। आपने बोलने का समय दिया महोदय इसलिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार । समय 2 मिनट ।

श्री अजय कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय ,मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को जिन्होंने बहुत मेहनत कर के इस बजट पेश किया गया है। महोदय, यह एक समावेशित बजट भी है और दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि आज बिहार के अंदर जो सच्चाई है, उससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं । उस बजट को और थोड़ा समृद्ध करने की जरूरत हम भी महसूस करते हैं । चूंकि बिहार किसानों का प्रदेश है और कृषि पर जो बजट इसमें रखा गया है जो परसेंट है, उससे हमको लगता है कि आज जो किसान उम्मीद पाले हुए है उससे उम्मीद

पूरा नहीं होगा । महोदय, मैं कुछ और बात कहना चाहता था, चूंकि हमारा टाईम बहुत कम है इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बजट के अंदर में एक चीज पर और थोड़ा सा ख्याल करने की जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा कि टीम वर्कर के बारे में भी कि उनकी जिन्दगी आज बहुत मुश्किल में है । अल्पवेतन भोगी वे लोग हैं, आठ घंटा काम करते हैं, उनका मेहनताना बहुत कम है इसलिए बिहार की जनता, गरीब जनता आप जब ज्यादा काम करते हैं तो आपसे उम्मीद भी ज्यादा पाले हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर जरूर खड़ा उतरने का काम कीजियेगा । जहां तक सवाल है, इस बजट के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी लोग जो बोलते हैं तो इन्हें इस पर बोलने का क्या हक है । अभी जो दिल्ली के अंदर बजट पेश की गयी है, उस बजट में क्या है, उस बजट में जिसके बारे में वे कह रहे हैं हमने लंबा और बड़ा बजट बनाया, गरीब हितेषी योजना पर जो बजट में खर्च हो रहा था उसमें कटौती करने का काम उन्होनें किया है । सबसे ज्यादा किसान के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, खेती अनुदान में जो है 33 प्रतिशत के बजट में कटौती भारतीय जनता पार्टी के नरेन्द्र मोदी के हुकूमत ने उसमें कमी किया है और जब 33 प्रतिशत के बजट में कटौती होगा तो इस देश के किसानों का क्या भविष्य हो सकता है । इस देश के किसानों की हालत क्या हो सकती है इसीलिए हम आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस देश के बजट अनदेखी कर के आप नहीं चल सकते हैं । बजट हमारा जो है मार्गदर्शक होता है, नीति निर्धारित होता है इसीलिए हम यह बात कहना चाहते हैं । अभी हमारे जो साथी बोल रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरू बनने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरू का सपना भी आप देख रहे हैं...

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अन्य सदस्यों को भी बोलना है आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अजय कुमार: मैं खत्म कर रहा हूँ । मैं सिर्फ इतना कह करके खत्म कर रहा हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरू का जो सपना देख रहे थे, आप हिरनवर्ग का जो है आप रिपोर्ट उसको देखिये और उसके बाद ग्लोबर हंगर के रिपोर्ट को देखिये। गरीबी में हमारा देश जो 2021 में 101 पर था और आज वह 2022 में 107 पर चला गया ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्षेत्रफल को न बढ़ावें इसलिए कि समय की कमी है ।
माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान। अपना पक्ष रखें, एक मिनट में ।

श्री अखतरूल ईमानः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने की इजाजत दी है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूॅ । इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार ने पिछले 10-15 सालों में तरक्की की है लेकिन बिहार की सरकार ने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है यह गलत है । वर्ष 2005-06 में बिहार का बजट 25 हजार करोड़ का था आज 2 लाख 61 हजार करोड़ का बजट है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन इंसाफ की जरूरत है सीमांचल विकास आयोग बनाने का वादा, इसी इंसाफ के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था वह पूरा नहीं हुआ । गंगा पर पुल बने लेकिन महानंदा में आज जहां सिल्ला, अभयपुर, कुट्टी, भयंकरद्वारी, निचितपुर, छतरघाट, कंकई के मटियारी, तालवारी, बकराघाट, बलबाघाट पर आजतक पुल नहीं बन सका है। परमान के बकराघाट और बलुआघाट पर पुल नहीं बन सका है । आर0डब्लू0डी0 का बजट बढ़ा है महोदय, मैं निवेदन करता हूॅ कि वसैली और खाड़ी का पुल पिछले 10 सालों से अधूरा पड़ा है, उसको पूरा किया जाय । प्रधानमंत्री सड़क की चर्चा की गयी है लेकिन मुख्यमंत्री सड़क और जी0टी0एस0एन0वाई0 की कोई चर्चा नहीं हुआ है। गांवों को जोड़ने का उपाय किया जाय । आपदा में आपने राशि बढ़ायी है लेकिन हजारों लोग जो विस्थापित हैं उनको आजतक मुआवजा नहीं मिल सका है 2459 प्लस 1 मदरसों में से 205 और 609 को तनख्वाह दी जा रही थी उसमें से 609 को बिना वजह जांच करके उसकी तनख्वाह रोकवा दी गयी है और 1645 पर अबतक कार्रवाई नहीं की गयी है, उस पर कार्रवाई की जाय । महोदय, सातवें चरण के शिक्षक की बहाली की जाय और महानंदा बेसिन की बात पिछले 12 वर्षों से सुनी जा रही है और अबतक जमीन पर उतारी नहीं गयी है उस एस्टीमेट में तब्दीली कर के जमीन पर उतारा जाय । महोदय, अगर बिहार में तरक्की हो रही है तो मजदूरों का पलायन क्यों हो रहा है, तमिलनाडू में मजदूरों की पिटाई क्यों हो रही है ? परकैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? सीमांचल आज सबसे गरीब क्यों रह गया है, सीमांचल को सैलाव की तबाही से निकालने का कोई उपाय क्यों नहीं हुआ है ? महोदय, एक बात कहकर मैं आपसे जुदा हो जाउंगा महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूॅ कि इंसाफ के साथ तरक्की का आपने दावा किया है तो इसी सदन में कमिटी बनाईए और सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है पिछले 75 सालों से उसका इंसाफ दिलाईए । संवेदनशील सरकार से यह आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी नहीं और बजट में कहीं ईशारा नहीं मिल रहा है कि सीमांचल को हक मिलेगा इसलिए

हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस मामले में कि सरकार को सुझाव जरूर देंगे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री संजीव चौरसिया । अपना पक्ष रखें 12 मिनट में ।

श्री संजीव चौरसिया: महोदय, मैं सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, मुख्य सचेतक जनक सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ । निश्चित तौर पर जब पेश हुआ तो मन को रहा कि काश, इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाय कि किसानों, इंसानों, बेरोजगारों का दिल खुशहाल कर जाय । पर सच में खुशहाल किस रूप में है, यह पता है लोगों को, जिस प्रकार से बजट की अपेक्षा और आकांक्षा थी, बिहार का दृष्टिकोण उसमें प्रदर्शित नहीं होता है। ये बजट अपने आप में परिलिक्षत करता है कि बिहार का दृष्टिकोण क्या है, कैसे है । केन्द्र की योजनाओं का अगर सफलीभूत नहीं हो तो बिहार का बजट अपने आप में सफलीभूत नहीं दिख सकता है । जिन योजनाओं पर दम भरने का काम हो रहा है, जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उसमें धन्यवाद तो केन्द्र सरकार को करना चाहिए कि 60 से 65 प्रतिशत से ज्यादा बजट का अगर योगदान है तो वह केन्द्र सरकार का है । महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दिशाहीन डपोरशंखी घोषणाओं का जो यह बजट है इसमें लोग समझ गये हैं कि 10 लाख नौकरियों का बार-बार झांसा देकर यानी कि जब उपमुख्यमंत्री और उस समय के आर0जे0डी0 के घोषणा पत्र में अगर प्रथम वरीयता के आधार पर जब आप रोजगार का सृजन करते तो 20-20 कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो क्या 10 लाख रोजगार के योजनाओं का किस प्रकार से दिख रहा है, क्यों छलावा करने का काम कर रहे हैं बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता समझ रही है बुझ रही है । ये तो पुरानी योजनाओं थी, जो पुरानी रिक्तियां थी जो एन0डी0ए0 सरकार में थी उसी को फिर से नया वस्त्र पहनाकर रिक्ति का अमलीजामा पहनाने का काम कर क रहे हैं, सिपाही से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सभी विभागों का अगर देखेंगे तो उन्हीं योजनाओं का आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपने आप को दम भर रहे हैं कि गरीब किसानों का, गांव के गरीबों का यह बजट है लेकिन यह दिख नहीं रहा है । जहां बजट के आकार को और आगे ले जाना चाहिए था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मूलभूत योजनाओं पर अधिक खर्च करने का काम करेंगे, वहीं घटाने का काम हुआ कि 38 प्रतिशत मात्र रखा गया कि हम बढ़ाने का काम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के आचार पर और 62 परसेंट के करीब वेतन के आधार पर वेतन स्थापना के दृष्टिकोण से रखा गया पर आज मूलभूत संरचना को जो बढ़ाने का काम करना

था जिसे रोजगार के सृजन होने का काम होता लेकिन वह 5 सौ करोड़ और घटने का काम हुआ है, इससे कतई नहीं देख सकते हैं , बिहार की जनता सोच सकती है कि रोजगार के सृजन बढ़ाने का काम कर सकते हैं । वहीं केन्द्र की सरकार ने 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर देने का काम किया । पुल पुलिया बांध सड़क अस्पताल सभी बनने का काम होगा । रोजगार का अवसर साफ दिखाई देगा । रोजगार का दृष्टिकोण दिखाई देता है तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार को भी घटाने का काम किये हैं इससे साफ दिखाई देता है कि दृष्टिकोण किस प्रकार का है, बिहार को क्या मिलने वाला है(क्रमशः)

टर्न-14/मधुप/03.03.2023

..क्रमशः..

श्री संजीव चौरसिया : जिस प्रकार आप देखेंगे कि बिहार में मेरे को अब इस बार लगभग बिहार को 25 हजार करोड़ केन्द्र से राशि मिलने का काम हो रहा है । इसका लाभ अपने को मिलने का काम हो रहा है । दृष्टिकोण जब स्पष्ट नहीं है तो वास्तव में इस बजट का न्याय हम नहीं कर पायेंगे । एक ओर सरकार कहती है कि हम रिक्तियों को भरने का काम करेंगे जो मैंने पूर्व में बताया अलग-अलग प्रकार से कि 12 हजार बी0पी0एस0सी0 की रिक्तियों को लेकर, अलग-अलग एजेन्सियों के माध्यम से, आप उन रिक्तियों का पिटारा दर पिटारा खोलने का काम करेंगे तो कहीं न कहीं जब सरकार में सम्मिलित थे तो उन्हीं रिक्तियों को हम आगे बढ़ाने का काम किये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शिक्षा की स्थिति है, कृषि की स्थिति है, माननीय नीतीश जी ने बताने का काम किया कि कृषि की स्थिति में अपनी क्या स्थिति है, बजट के प्रावधान में अगर उसको देखेंगे तो वहाँ भी परिलक्षित होने का काम हो रहा है । स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वृद्धि जिस अनुपात में होनी चाहिए, नहीं होने का काम हुआ है । जो प्रमुख 10 विभाग हैं, उन 10 विभागों में जिस अनुपात से वृद्धि होनी चाहिए, वह वृद्धि होने का काम नहीं हो पाया है तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय पर अगर हम देखेंगे तो जो शिक्षा महत्वपूर्ण दिशा तय करने वाला बिहार प्रांत है कि जहाँ चाणक्य की धरती, चन्द्रगुप्त की धरती, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय का रहा है, आज सब प्रकार से देखेंगे तो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किये हैं पर बेंच-डेस्क की जब बात करते हैं, लड़कियों के शौचालय की बात करते हैं, लड़कियों के पोशाक योजना की जब बात करते हैं तो अलग-अलग प्रकार से करने का काम हम करते हैं पर क्या आप

देखेंगे कि उन स्कूलों में शौचालय की उपलब्धता है क्या ? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आंकड़े बताते हैं विद्यालयों में प्ले-ग्राउंड नहीं है, लड़कियों के लिए शौचालय के दृष्टिकोण से जो होना चाहिए, वह नहीं है तो एकमात्र इंफ्रास्ट्रक्चर दे देने से काम नहीं चलने वाला है । उसकी गुणवत्ता के आधार को बनाने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कहना चाहेंगे आपकी दृष्टि से कि संस्कृत बोर्ड से लेकर जितने बोर्ड हैं, मैथिली समाज से लेकर भोजपुरी एकेडमी से लेकर सभी जगह पर अध्यक्ष के पद अभी तक खाली हैं । क्या कठिनाई है आपको करने में ? अगर करते तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती, उसकी दिशा बनती, उन भाषाओं को आगे बढ़ाने का काम होता है पर दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाने का काम करना है । उसी की परिणाम और परिणति दिखाई दे रही है । आज जो बनना चाहिए था नहीं बन पाया । इंजीनियरिंग कॉलेज की जब बात करते हैं तो क्या परिणाम है, क्या स्थितियाँ हैं ? पढ़ाई की स्थिति क्या है कि 460 छात्र से ज्यादा फेल होने का काम करते हैं । कहीं न कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से बिहार की चरमराने का काम करने का काम किया है । अलग-अलग प्रकार से देखेंगे तो सभी प्रकार की स्थिति में आगे बढ़ने का काम हो रहा है । मिलेट पर इंटरनेशनल मिलेट घोषणा करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया । उसका अनुपालन कराने का काम आप कर रहे हैं पर उसके तहत जो देनी चाहिए थी, उन योजनाओं को आगे करने का काम आपने नहीं किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहेंगे कि जिन आवंटनों को उनको बढ़ाने का काम करना चाहिए था, हम बढ़ाने का काम नहीं किये हैं । माननीय एक वक्ता अपने मित्र माननीय विधायक जिन बातों को कह रहे थे, उन बातों पर हम स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे कि एस0सी0 समाज को फ्री स्कॉलरशिप कार्ड देना चाहिए था, वह बिहार की सरकार ने कार्ड देने का काम नहीं किया है जो और प्रांतों में हुआ है । अगर सी0ए0जी0 ने इस बात को रिपोर्ट किया है तो उसका पुख्ता प्रमाण अपने पास है कि कितने-कितने करोड़ का डायवर्सन ऑफ फंड हुए हैं रोड में, सड़क में करने का काम किया है। क्या यही न्याय है ? क्या एस0सी0 समाज के साथ विश्वासघात नहीं है ? सी0ए0जी0 के रिपोर्ट में आपने मानने का काम किया है बिहार सरकार ने कि हम किस प्रकार से उस फंड के डायवर्सन करने का काम किया है और कोर्ट के अन्दर बताने का काम किये हैं कि हम ऑलरेडी जो स्कीम है उस स्कीम के माध्यम से, फायनेंशियल स्कीम के माध्यम से हम देने का काम करते हैं पर वह लोन के माध्यम से देने का काम करते हैं । जो फ्री स्कॉलरशिप देने का काम करना है, फ्री

जो कार्ड बनना चाहिए स्कीम कार्ड, वह नहीं बनने का काम हुआ है । इसी के कारण से केन्द्र सरकार के जो मापदंड हैं, उस मापदंड पर उतरने का काम नहीं हुआ है । इसकी वजह से पदाधिकारियों की जो स्थिति रही है, वह बिहार सरकार स्वयं जानती है कि अंदर के तहखाने में झांक कर देखें कि हम एस0सी0 समाज के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं ? लाखों-लाख छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कीम के तहत लाखों छात्र अभी तक उससे महरूम हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है । अध्यक्ष महोदय, जहॉं तक अति पिछड़ा समाज की बात है, बताना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज के लिए जो योजना कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के अन्तर्गत देने का काम 32 जिलों में हुआ था, जननायक छात्रावास संचालित होने का काम है, उनकी स्थिति क्या है ? क्या सरकार बताने का काम करेगी कि कितने छात्र उसमें पढ़ रहे हैं ? छात्रों की संख्या वहॉं कम होते चली जा रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है । जहॉं अति पिछड़ा समाज की दृष्टि से 1878 करोड़ की राशि पिछली बार आवंटित की गयी थी, वहीं 1787 करोड़ का आवंटन देकर 100 करोड़ कम करने का काम अति पिछड़ा समाज के साथ किस विश्वासघात के साथ करने का काम किये हैं, यह बजट का प्रावधान बताने का काम करता है कि सरकार की योजना के अन्तर्गत ही समाज को कैसे आप छलनी करने का काम किये हैं, केवल एक मुखौटा बनाकर अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति वर्गों को जो आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, कतई नहीं हो सकता है क्योंकि बजटीय प्रावधान में इस बात के दृष्टिकोण दिखाई देने का काम कर रहे हैं । आप उद्योग की दृष्टि से बताने का काम कर रहे हैं, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया मेरे क्षेत्र में है । जिस प्रकार से आवंटन की बात होनी चाहिए, आवंटन होने का काम क्षेत्र का नहीं हो रहा है, रद्द की जा रही हैं, उनकी जमीन रद्द की जा रही हैं । जिस प्रकार से वे तंग आ रहे हैं तो आज उद्योग की दृष्टि से भी हमको जो करना चाहिए, समाज के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम नहीं होने का काम हो पा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कंक्लुड कीजिए ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि नगर विकास की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो नगर विकास में स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत पटना सबसे बड़ा उदाहरण है पर पटना में नालों के जो पाटने का काम टेन्डर की प्रक्रिया भी अभी नहीं हुआ है, बाबा चौक से लेकर बड़े-बड़े स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जो बड़े नाले इस प्रकार से खुले हैं, उसके टेन्डर की प्रकिया में सरकार करने का काम नहीं कर रही है । आज जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, यहॉं आपके प्रखंडों में पर्यावरण के जॉंच केन्द्र

खुलने का काम नहीं हुआ है तो किस गलतफहमी में यह सरकार जीना चाहती है कि हम पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । सबसे प्रदूषित शहर के नाते पटना किस प्रकार से परिलक्षित है वह बिहार की जनता, पटना की जनता जान रही है कि अब पर्यावरण से हाय-तौबा जिस प्रकार से मचने का काम हुआ है, पर्यावरण की दृष्टि से भी देखेंगे ।

सबसे बड़ा विषय आज दिव्यांग के विषय पर अगर देखेंगे कि दिव्यांग को जो स्टाइपेन मिलता है, वह सबसे कम बिहार को मिल रहा है । मैंने भी पिछले सत्र में सदन में प्रश्न उठाने का काम किया था कि दिव्यांगों को न्याय कब मिलेगा, दिव्यांगों की राशि ज्यादा करने का काम कब होगा ? पर यहाँ की सरकार ने उस योजना को भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है । महोदय, आपको यही बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात जो है कि -

''जिन्दगी एक अभिलाषा है, अपने-आप में परिभाषा है,
सम्भल गये तो जिन्दगी, नहीं तो एक तमाशा है ।''

हमें तमाशा नहीं बनने देना है, बिहार के जिस लक्ष्य को हम आगे ले जाना चाहते हैं, स्वर्णिम इतिहास के प्रणेता के रूप में जिस प्रांत को आगे ले जाना चाहते हैं, उसको हमको सही मायने में आगे ले जाने का काम करना है और छलने का काम नहीं करना है । महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी कि जो आपने बोलने के मुझे समय दिया । बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो इस बार बजट पेश किया गया है, लोकोपयोगी बजट जो इस बार पेश किया गया है, इतना बड़ा बजट है, पिछले बार से इस बार के बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है और बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है । बहुआयामी विकास करने की बिहार की जो नींव रखी गयी है और बिहार सरकार की जो शिक्षा पर नीति रहती है, शिक्षा को जो दलित बस्ती, जो गाँव के प्राथमिक विद्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया गया है, 99.8 प्रतिशत जो प्राथमिक विद्यालयों से गाँव और कसबों को दलित बस्ती को जोड़ दिया गया है ताकि समाज के अंतिम पायदान के बच्चे की भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है, यह सरकार की बहुत ही मजबूत पहल है और बजट में जिस तरह से शिक्षा पर जोर दिया गया है और प्राथमिक विद्यालय और ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है,

निश्चित रूप से पंचायत स्तर पर हमारी बच्चियॉं एजुकेट हो रही हैं और सरकार तो हमेशा से समाज के हर वर्ग की बात करती है । शिक्षा की बात करूं, सशक्तिकरण की बात करूं तो महिला सशक्तिकरण का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बहुप्रतिष्ठित योजना रही है जीविका, यह जीविका क्या है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस गॉंव-कसबों की उठी हुई महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अति सराहनीय पहल रही है जो गॉंव-कसबों में देखने को मिल रहा है कि आज हमारी महिलाएँ कैसे आर्थिक सम्पन्न हो रही हैं, कैसे सशक्त हो रही हैं और कैसे आगे बढ़ रही हैं जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को नौकरियों में और पंचायती राज में आपने 50 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की है, नगर निकायों में जो आरक्षण देने की पहल की है, यह पहल क्या है । यह आधी आबादी को सशक्त करने की जिसका जीता-जागता उदाहरण हमारे गॉंव में देखने को मिल रहा है, हमारे नगरों में देखने को मिल रहा है और बिहार में देखने को मिल रहा है क्योंकि बच्चियॉं आज पुलिस के रूप में बहुत छोटी-छोटी बच्चियॉं जब आ रही हैं, देख रहे हैं हमलोग तो बहुत खुश दिखती हैं

..क्रमशः..

टर्न-15/आजाद/03.03.2023

..... क्रमशः .....

श्रीमती संगीता कुमारी : और एक नाम लेती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से आज हमलोगों को देखिए, हमलोग आज पुलिस बन गये हैं, आज हमलोग ये बन गये तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकवाद देना चाहेंगे, जो इन्होंने एक मजबूत महिलाओं को सशक्त किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का यह एक बहुप्रतिक्षित योजना थी कि जातीय जनगणना कराने की कि बिहार में पूरी आबादी किनकी है और किस तरह से हम सबका विकास करें, जिस तरह से हमारी सरकार कहती है और हमलोग सबके विकास पर भरोसा रखते हैं, उसका विकास कैसे हो ? उसकी एक मजबूत पहल करते हुए जातीय जनगणना हमारी सरकार करा रही है । यह समाजवादियों की धरती रही है और जिस तरह से केन्द्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, वरना जिस दिन अगर बिहार को आज से नहीं, बहुत पहले से कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर केन्द्र सरकार दे देती तो बिहार की रूप-रेखा आज कुछ अलग होती तो कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार केन्द्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ

किया जाता है । लेकिन हमारी सरकार अपने दम पर बिहार को आगे ले जाने की पहल कर रही है । चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो । आर्थिक दृष्टिकोण से .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपनी बात जारी रखें । आप बोलते रहें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अल्पसंख्यक महिलाओं को 10हजार से बढ़ाकर 25हजार की राशि दी है, इस योजना के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है । इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए । अभी जो बिहार में सरकार चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं । जो उप स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत स्तर पर था, हमारी सरकार उसपर ध्यान दे रही है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब से स्वास्थ्य मंत्री का कमान संभाले हैं, तब से स्वास्थ्य क्षेत्र में टारगेट-60 के तहत सदर अस्पताल की नक्शा ही बदल कर रख दिया, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और यहां पर हमारी सरकार धार्मिक उन्माद फैलाने की बात नहीं करती है । आप देख रहे हैं कि आज इस देश में किस तरह से धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर अल्पसंख्यक ठगे जाते हैं, दलित घोड़े से उतार दिये जाते हैं । याद रखिए कि यह सदन है, धार्मिक सहिष्णुता के नाम पर अगर समाज में और देश में धार्मिक उन्माद फैल गया तो इस देश की रूप-रेखा अलग हो जायेगी, कोतूहल मच जायेगा और इसके बारे में जो चार पंक्तियां कहना चाहूंगी, जो आबो हवा फैलायी जा रही है कि -

यह न तेरा है, यह न मेरा है, यह हिन्दुस्तान सबका है,
नहीं समझी गई बातें, तो नुकसान सबका है ।
जो इसमें मिल रही नदियां, दिखलायी नहीं देती,
वहां सागर बनाने में, मगर एहसान सबका है ।

यह धर्म, यह भारत की पृष्ठभूमि है, यह भारत की राष्ट्रीयता है । यहां देश को स्वतंत्र कराने वाले लोग बैठे हैं । माननीय कर्पूरी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के नीतियों पर चलने वाले लोग हैं और हमलोग बाबा साहेब अम्बेडकर के नीतियों को साकार करने वाले लोग हैं । हमलोग इस देश में गोडसे और गोलवलकर की नीतियों को कभी भी चलने नहीं देंगे । यह देश चलेगा, यह भारत के संविधान के तहत चलेगा और यह देश गॉधी जी के नीतियों से चलेगा । इस देश में कभी भी धार्मिक उन्माद फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से आबो हवा फैलायी जा रही है, महंगाई की बात कहते हैं । इस देश में तो अदाणी को मजबूत

किया जाता है, इस देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ किये जाते हैं, किसानों के कर्जे माफ नहीं किये जाते हैं । खाने वाली चीजों पर टैक्स पर टैक्स लगा दिया जाता है, पेट्रोल पर टैक्स पर टैक्स लगा दिया जाता है और उनके द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है । हमलोग किस तरह से कहां पर सरकार गिराये, इसकी योजना बनायी जाती है । आम व्यक्ति को आज महंगाई का मार झेलनी पड़ रही है और हमारी सरकार जो काम कर रही है, वह निश्चित रूप से यह जंगलराज नहीं, मंगलराज है । सुशासन की सरकार है और आज मैं कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन और प्रशासन पर अपने सभी वर्गों में पहचान बनाये हुए हैं । अब मैं पहले की भी बात कहना चाहूंगी, 1990 के समय की बात कहना चाहूंगी, उस समय भी समाज में इस तरह का धार्मिक उन्माद, समाज का एक वर्ग कभी डरा हुआ महसूस नहीं करता था । जिस तरह से भारत की आज की जो स्थिति है और हमारे बिहार की बजट में सब लोगों की समावेशी विकास की बात हो रही है और हमारी सरकार इसी पर चल रही है । हम सभी वर्गों के विकास की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम ए टू जेड की बात करते हैं और उसी को देखते हुए हमारी सरकार ने बजट पेश किया है । उसमें शिक्षा की बात की गई है, उसमें सुरक्षा की बात की गई है, उसमें स्वास्थ्य परियोजना की बात की गई है, मैं आंकड़ों के जाल में न पड़ूं तो सरकार का इसपर पूरा ध्यान है और पहली बार सरकार ने बजट में रोजगारोन्मुखी बजट सरकार ने पेश किया है । जिस तरह से हमारे नेता ने रोजगार का वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वह कहीं न कहीं इस बजट के माध्यम से उसको पेश करने की बात की है और 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए इस बजट में पेश किया गया है और उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और दस लाख हमलोग युवाओं को नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार का हम सृजन करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार आज यह पहली बार देख रहा है । बिहार यह पहली बार देख रहा है कि बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है । धर्म की बात नहीं कही है, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की है, किसानों के हित की बात कही गई है । पहली बार बजट में इन बातों का जिक्र किया गया है कि 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार रोजगार देगी, बिहार का युवा उप मुख्यमंत्री जो रोजगार की बात करते हैं, उन्होंने साबित करने का काम किया है। आप देख लीजिए कि युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां

देंगे । बिहार के 32 प्रतिशत आबादी जो युवाओं की है, वह आशा रखती है, विश्वास रखती है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर, इनपर विश्वास रखती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी बात सुनेंगे और युवा उप मुख्यमंत्री हैं, जरूर सुनेंगे । देख लीजियेगा, आगे-आगे देखिए । युवाओं का देश आज है । लोगों को बिल्कुल रोजगार मिलेगा ।

आये दिन हमलोग देख रहे हैं कि जो हमारी महिलायें हैं, टोला सेवक हैं, जितनी हमारी जीविका दीदियां हैं, आशा हैं, सभी कर्मियों को आज काम मिल रहा है । जितनी .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्यकर्मियों को काम दिया है, रोजगार दिया है । हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी से इस बजट के माध्यम से नौकरियों का सृजन किया है, नौकरी भी देंगे और रोजगार भी देंगे और नये-नये अवसर दिखायेंगे और बिहार की जनता और बिहार का युवा आज हमारी सरकार पर विश्वास करता है । मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय को ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा जी । 5 मिनट , अब बोलिए ।

श्री रत्नेश सादा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट के आय-व्यय पर मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ । मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री दक्षिण बिहार में जो जल का अभाव था, पटवन का अभाव था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल योजना लागू करके दक्षिण बिहार के लोगों को राहत देने का काम किया, यह भागीरथी प्रयास है महोदय । आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह काम हुआ है ।

महोदय, गरीब-गुरबा के कल्याण के लिए सात निश्चय योजना चलाकर पक्की नली, पक्की सड़क और शुद्ध पेयजल देने का काम किया गया है । माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने आज बिहार में सड़कों की जाल बिछा दी है और इतना ही नहीं महोदय, हर क्षेत्र में विकास करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दलित-महादलितों के लिए उन्होंने 3 डिसमिल जमीन देकर के और एक नया इतिहास रचने का काम किया । महोदय, महादलित विकास मिशन के तहत दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देकर के रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है । इतना ही नहीं महोदय, महादलित बच्चों के लिए पोशाक राशि का व्यवस्था किया गया, बच्चियों के लिए साईकिल की व्यवस्था किया गया .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सादा जी, अब जो है माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो है, आप अपना स्थान ग्रहण करें । चूँकि माननीय श्री शकील साहेब को बोलवाना है ।

माननीय श्री शकील अहमद खाँ जी, तीन मिनट ।

श्री शकील अहमद खाँ : बहुत-बहुत शुक्रिया सर । मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ और नेता प्रतिपक्ष का मैं शुक्र गुजार हूँ कि कल उन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे श्री कृष्ण बाबू का नाम लिया और उनकी तारीफ की तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ । जब माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया तो मैंने देखा कि प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ छींटाकशी हो रही थी तो सर के लिए मैं एक शेर भतृहरि का याद आया, आपकी बातें फूल की तरह है -

फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
मर्दे नादां पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर ।

हमारी सरकार इंसाफ के साथ न्याय करती है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-16/शंभु/03.03.23

श्री शकील अहमद खां : क्रमशः हमारी सरकार अपने बजटरी प्रोविजन्स में इस बात का ख्याल रखती है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो । हमारी आर्थिक नीतियां ऐसी नहीं होती है कि चन्द मकसूस लोगों के घर धन और दौलत से भर जाएं जिसमें आज के दिन में अडानी और अंबानी बहुत मशहूर हैं । हमारी सरकार इंसाफ और अदल की बात पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनोरिटीज, महिला और अपर कास्ट सबके लिए सर्वांगीण विकास की बात करती है । इसीलिए हम इसके पक्ष में खड़े हैं । विपक्ष के साथियो, मैं अपनी सरकार के लिए भी एक शेर कहना चाहता हूँ इकबाल का शेर है- कि अब हमले होते रहते हैं इस हमले के खिलाफ- हमला कौन सा जो वाद विवाद का हमला है कि-

नशेमन घर नशेमन तू इस कदर तामिद करता जा ।
नशेमन घर यानी घोसला,
नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामिद करता जा
कि बिजली गिरते-गिरते आखिर बेजार हो जाय ।

वो बेजार हो जाय । अब मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ इतिहास के पन्नों से क्योंकि इसका जिक्र यहां हुआ है । यह बहुत जरूरी है क्योंकि सारी चीजें रेकार्ड

होगी । लड़ाई तो असल में विचारधारा की है । वैचारिक लड़ाई से ही हमलोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को यहां तक लेकर आये हैं । कुछ सुन लिया जाय हमलोगों को तो देशद्रोही कहा जाता है । हमलोग इनको छद्म राष्ट्रवादी कहते हैं तो यह चलता रहेगा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण पेज वाइज नाम के साथ और साक्ष्य के साथ कहना चाहता हूँ । तिरंगा झंडा जिसको हम सब सलाम करते हैं जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, हमारी मिसाल है वो । उसके प्रति अब जरा सुनते जाइये । 14 अगस्त, 1947 के अंक में राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंग्रेजी के अपने मुख्यपत्र आर्गेनाइजर- ये आर0एस0एस0 का मुख्य पत्र है आर्गेनाइजर । टाइम दे रहा हूँ डेट दे रहा हूँ 14 अगस्त, 1947 के अंक में राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे के चयन की खुलकर भर्त्सना करते हुए लिखा कि वे लोग जो किस्मत के दाव से सत्ता तक पहुंचे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में मारे जाने वाले लोग किस्मत के दाव से पहुंचे थे कि लड़कर पहुंचे थे । स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर वे लोग जो किस्मत के दाव से राज्य की सत्ता तक पहुंचे हैं वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिन्दुओं द्वारा न कभी इसे सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा । इसीलिए 52 साल तक आर0एस0एस0 के हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया गया, यही सत्य है । आप आगे सुनिए 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो यह खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा । हमें छद्म राष्ट्रवाद ? सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

श्री शकील अहमद खां : उसके बाद गोलवलकर ने लिखा आप सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आपको जो कहना होगा कहियेगा । वे जो कह रहे हैं रेकर्ड से बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री शकील अहमद खां : गोलवलकर ने लिखा ।

अध्यक्ष : वे अपने भाषण के क्रम में बोल रहे हैं । माननीय सदस्य खान साहब, अब आपका समय समाप्त हुआ और माननीय वित्त मंत्री जी अब बोलेंगे । कन्क्लुड कर दीजिए।

श्री शकील अहमद खां : नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हां कन्क्लुड कर रहा हूँ । सरदार पटेल जी हमलोगों के नेता हमारे ऐतिहासिक पुरूष लौह पुरूष ने चिट्ठी लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वह चिट्ठी लिखकर के जब आर0एस0एस0 को बैन किया गया तो क्या लिखा सुन लीजिए । सरदार पटेल ने 18 जुलाई 1948 को ये चिट्ठी लिखा- जहां तक आर0एस0एस0 और हिन्दु महासभा की बात है गांधी जी के हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमें मिली रिपोर्ट के मुताबिक यह पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का खासकर आर0एस0एस0 की गतिविधियों के फलस्वरूप.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श पर अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

आप सभी लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय वित्त मंत्री की बातों को आप सुनें । आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय वित्त मंत्री जी, आप अपना भाषण शुरू करें ।

(व्यवधान)

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में हमने 28 फरवरी को आपकी इजाजत से वर्ष 2023-24 का बिहार सरकार का आय-व्ययक अनुमान पेश किया था । इसपर पिछले दो दिनों से चर्चा चल रही है, चर्चा सार्थक हुई है । महोदय, आप जानते हैं कि बजट इतना महत्वपूर्ण होता है कि पूरा सत्र बजट सत्र कहलाता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी का बजट भाषण हो रहा है । आप स्थान ग्रहण करें आपको कहना था वह आपने कल भी कहा और आज भी कहा ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कीजिए न कि आप देख लीजिएगा और अगर कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसको निकाल दीजिएगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं बार-बार इनलोगों से कहता हूँ कि अगर कोई आपत्तिजनक बात माननीय सदस्यों के द्वारा कहे गये हों तो हम प्रोसिडिंग देख लेंगे और अगर वह असंसदीय है, गलत है तो उसको कार्यवाही से मैं निकलवा दूंगा । आप बैठ जाइये।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : चलिए हो गया अब ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे क्या चाहते हैं भाई अब । गलत होगा उसको मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा । कार्यवाही से मैं निकलवा दूंगा । अब क्या कहें बोलिये । अब क्या कहा जाय । मैं देखवाउंगा और अगर गलत होगा तो कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री जी, आप अपना भाषण करें । इन लोगों का यही कार्यक्रम है, आप भाषण करें । बजट भाषण आप करें । इन लोगों को बजट से कोई मतलब नहीं है, आप भाषण करें ।

(व्यवधान)

आपत्तिजनक होगा उसको मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा । निकलवा दूंगा कार्यवाही से।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण ने सदन से वॉक आउट किया।)

चलिए, आपलोगों को संसदीय व्यवस्था से कोई मतलब है क्या ? माननीय मंत्री जी, शुरू करें ।

टर्न-17/पुलकित/03.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इनको न बिहार से मतलब है और न बिहार की जनता से मतलब है और जब जनता से ही नहीं मतलब है तो बजट से क्या मतलब रहेगा ।

अध्यक्ष : इन लोगों को बजट से क्या मतलब है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने कहा कि पिछले दो दिनों से जो हमने 28 फरवरी को इसी सदन में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया था । यह सदन पिछले दो दिनों से उस पर विमर्श कर रहा है । महोदय, उसके पहले जो कल और परसों, परसों और तरसों यानी 28 तारीख को और 01 तारीख को महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण 27 तारीख को हुआ था, उस पर माननीय सदस्यों ने विमर्श किया और हमलोगों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया और कल से आज जो बजट हमने 28 तारीख को पेश किया था उस पर सदन

विमर्श कर रहा है और अंत में मैं सरकार की तरफ से अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, अमूमन ये दोनों चीजें महामहिम का अभिभाषण और बजट का जो प्रस्ताव होता है । ये दोनों मतलब सहगामी होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं क्योंकि महामहिम राज्यपाल जो हमारी सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं, जो नीतियां होती हैं, जिन सिद्धांतों पर हम बढ़ना चाहते हैं, वे उसको रेखांकित करती हैं और बजट का प्रस्ताव जब हमलोग सदन में लाते हैं तो महामहिम ने जो सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई हैं या जिन बातों की चर्चा उन्होंने की है हम उनको कैसे क्रियान्वित करेंगे, उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करेंगे । कितना धन कहां से लायेंगे और कितना धन किन योजनाओं पर, किन प्राथमिकताओं पर खर्च करेंगे, यह ब्यौरा हम सदन में रखते हैं और सदन से अनुमति मांगते हैं । महोदय, दो दिनों से बहस चल रही है । समझिये नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगभग पन्द्रह सदस्यों को आपने इस पर अपने विचार रखने की इजाजत दी और सभी लोगों ने अपने विचार रखें हैं । महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की बातों को जो उन्होंने कहा लेकिन अब तो वे हैं ही नहीं । हम तो चाहते थे कि वे रहें । जो उन्होंने कहा है उसमें सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है ? एक तो वे हैं नहीं, हम तो चाहते हैं कि वे जहां भी रहे जरूर सुनें क्योंकि जिस ढंग से बिहार की जनता को धोखा दिया जा रहा है या केन्द्र सरकार के द्वारा जो लगातार नाइंसाफी की जा रही है । हम उसको परत-दर-परत खोलकर सदन के सामने रखना चाहते हैं । इसलिए भी हम उन बातों की चर्चा करेंगे ही लेकिन उसके पहले हम एक चीज कहना चाहते हैं कि पार्टी के प्रति निष्ठा एक चीज होती है, पार्टी के प्रति विश्वास एक चीज होती है, पार्टी के प्रति अंध विश्वास, अंध समर्पण यह तीसरी चीज होती है लेकिन अंध समर्पण आका के सामने या पार्टी के सामने इस किस्म का हो जाए कि हम अपना वजूद, अपनी अस्मिता ही भूल जाए, महोदय, तब ये बड़ा घातक होता है, बड़ा कष्टदायी होती है और यही हाल है हमारे भाजपा के साथियों के साथ । अपने आका के स्तुति गान में वे भूल जाते हैं कि वे बिहार, बिहार की मिट्टी और बिहारीपन का अपमान करने से नहीं चूकते हैं अपने आका को खुश करने के लिए । आप सोचकर देखिये अभी पिछले कुछ दिनों से कैसे-कैसे बयान आ रहे हैं जब से केन्द्रीय बजट आया है । यहां के नेताओं के बयान तो छोड़िये दिल्ली तक के नेताओं के क्या-क्या बयान आये हैं । एक ने कहा कि केन्द्र पैसा देना बंद कर दें तो बिहार की बत्ती गुम हो जायेगी । एक ने कहा कि हम पैसा दे दें, नहीं दे तो ये लोग कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे । एक महोदय यहां के वित्त मंत्री रहे हैं, मुझे

आश्चर्य ही नहीं हुआ बल्कि अफसोस भी हुआ, जब हमने उनका बयान देखा कि वर्ष 2023-24 के बजट में केन्द्र सरकार, बिहार को एक लाख करोड़ रूपये देगी, मदद करेगी विकास करने के लिए । महोदय, वे वित्त मंत्री रहे हैं, वे जानते हैं बात वे सही कहे हैं, उस बात को हमने कहीं नहीं छिपाया । हमने जो बजट में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उसमें हमने उसका उल्लेख किया है लेकिन वे हमको मदद नहीं कर रहे हैं । वे कोई हमको दान नहीं दे रहे हैं, वह हमारा हिस्सा है । वह हमने लिखकर दिया है कि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है, यह संवैधानिक व्यवस्था है और उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे एक लाख करोड़ वे दे रहे हैं । महोदय, एक पैसा तो वे देने वाले नहीं हैं और हमारा दस पैसा रोक जरूर सकते हैं लेकिन कहते हैं कि एक लाख करोड़ रूपये दे रहे हैं । महोदय, मुझे बड़ा घोर आश्चर्य हुआ, हम तो सदन से निवेदन करना चाहते हैं और बिहार की जनता को भी कहना चाहते हैं कि भाई हम जितने बिहारी लोग हैं, हमलोग बिहारी लोग किसी के रहमों-कर्म पर नहीं जीते हैं, किसी के दान और खैरात पर नहीं जीते हैं । हमलोग अपनी किस्मत लिखने वाले लोग हैं, हम लोग अपनी मेहनत से किस्मत बनाते हैं । अभी शकील साहब इतने शेयर पढ़ दिये, पता नहीं चला इसलिए हमें भी दो बात याद आ गयी । दो-चार पंक्तियां हैं इसके बारे में, बिहारी खुद्दारी जो होती है, बिहारी स्वाभिमान जो होता है, बिहारी आत्मबल जो होता है उसके लिए बिहारी की तरफ से कहा गया है कि :-

''न रहा मैं कभी मोहताज चांद-सितारों का,
हमने अपनी मेहनत से उजाले देखे हैं,
तस्कीरा लकीरों का उसने वहीं छोड़ दिया,
जब नजूमी ने मेरे हाथ के छाले देखे ।''

महोदय, इन पंक्तियों में वही दम है, जो बिहारियों में दम होता है । हम अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से लिखते हैं । हम किसी की कृपया पर नहीं जीते हैं और हमको किसी ने आजतक कुछ किया भी नहीं है । हमलोग तो मदद करने की तो बात छोड़िये, अपना हक, हिस्सेदारी मांगते रहते हैं, वह नहीं मिलता है । महोदय, अब तो वे चले गये, हम तो उनको बताने वाले थे कि जो उन्होंने कहा हमारी सरकार आई तो केन्द्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है उसको हमने 32 से 42 प्रतिशत कर दिया । महोदय यह बात सही है लेकिन शायद अपने नेता की चालाकी और उनकी पेचीदगी का इनको खुद भी एहसास नहीं है कि कैसे वे छलते हैं और उस छलावे के पीछे स्थिति यह है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि वे जो 42 प्रतिशत कह रहे थे, 42 प्रतिशत जो उन्होंने किया है तो वर्ष 2000

से 2005 तक महोदय जो पूरे टैक्स की राशि होती है, जिस समय 32 प्रतिशत था, उस समय बिहार को लगभग 14.50 प्रतिशत प्राप्त होता था । वर्ष 2005 से 2010 तक 11 प्रतिशत प्राप्त होता था और महोदय, जब 2015 में 42 प्रतिशत कर दिये तब हमारा प्रतिशत घटकर 9.6 प्रतिशत ही रह गया । महोदय, वह कलाकारी, कलाबाजी है कि वर्टिकल डिवीजन जो कहते हैं केन्द्रीय करों में राज्यों का कुल हिस्सा वह तो 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कर दिया लेकिन राज्यों के बीच बंटवारे का जो उपबंध किया, जो तरीका अपनाया उसमें हमारी स्थिति यह हो गयी कि हमें जो मिलता था जैसा कि हमने बताया कि 11 से 10.5 प्रतिशत मिलता था वह इनके लागू करने के बाद 9.6 प्रतिशत हो गया । ये तो इनको समझ है नहीं और महोदय, इतने तरह के इसमें जाल बुने गये हैं, हम आपको और बताना चाहते हैं । जो इन्होंने टैक्स की बात कही है सरचार्ज की ।

(क्रमशः)

टर्न-18/अभिनीत/03.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, 25 नवम्बर को प्री-बजट इंटरेक्शन जो राज्य के वित्त मंत्रियों से केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, उसमें हमने निर्मला सीतारमण जी जो देश की वित्त मंत्री हैं उनको हमने कहा था, ये सारी बातें कहीं, जितनी बिहार की तरफ से बातें हैं वे सब बातें हमने 25 नवम्बर को दिल्ली में जो निर्मला जी के साथ, जो बजट से पहले उन्होंने विमर्श किया था और फिर अभी 18 फरवरी को उन्होंने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी उसमें भी हम बिहार की तरफ से गये थे और हमलोगों ने अपनी बातें रखीं कि आप हमको जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है वो क्यों नहीं देते हैं ? अब ये तीन तरह से जाल बुनते हैं । महोदय, हमारे पास आंकड़े हैं, ये कहते तो हैं 42 प्रतिशत, महोदय राज्यों का तीन तरह से शोषण किया जाता है । केंद्र सरकार जो वित्तीय व्यवस्था में जाल बुनती है उसमें राज्यों का तीन तरह से शोषण होता है, खासकर बिहार जैसे राज्यों का । सबसे पहला, जो वो कहते हैं कि 42 प्रतिशत, आजतक कभी भी 42 प्रतिशत उन्होंने डिवाल्व किया ही नहीं, दिया ही नहीं है । जो पूरे राज्यों के लिए, सभी राज्यों की बात मैं कह रहा हूं । खैर वे सभी राज्य में ही जब कम देते हैं, तो ऐसा पैमाना बना दिया है कि बिहार को तो वैसे भी कम हिस्सा मिलता है । जब सभी राज्यों को मिलने वाली राशि ही घट जाती है तो स्वाभाविक रूप से बिहार का हिस्सा और घट जाता है । महोदय, ये जो कह रहे हैं 42 प्रतिशत, हमारे पास आंकड़े हैं 2015-16 से लेकर 2018-19 तक, ये कहते हैं 42 लेकिन इन्होंने मात्र 35 से 37 प्रतिशत तक ही राशि नीचे मतलब अंतरण डिवाल्व किया है ।

उसी तरह से महोदय, 2019-20 में ये 42 की जगह पर मात्र 32 प्रतिशत ही इन्होंने डिवाल्व किया है और जब से 15th फाइनेंस कमीशन लागू हुआ है, 2020-21 में 42 के बदले 29 प्रतिशत दिया है नीचे । महोदय, हम तो चाहते थे कि जरा रहते तो हम पूछते कि इनको तो समझा दिया जाता होगा कि हम तो 42 प्रतिशत दे दिए हैं लेकिन देते हैं 29 प्रतिशत । 2021-22 में 33 प्रतिशत, 2022-23 में 31 प्रतिशत और महोदय अभी 2023-24 का बजट जो तुरंत पार्लियामेंट में पेश किया गया और पास किया गया है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके इस्टीमेट में जो केंद्रीय कर का हिस्सा राज्यों को डिवाल्व होना है यानी जो वे क्लेम करते हैं कि 42 प्रतिशत हम देते हैं, उसमें प्रोविजन ही किया गया है 30 प्रतिशत का । अब सोच लीजिए यह तो नाइंसाफी के साथ-साथ बेईमानी है । अभी कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी सरकार ने ही किया है और करके, इसमें तो जो हमने कहा महोदय कि तीन तरीकों से राज्यों का शोषण करके राज्यों को वित्तीय दबाव में रखा जाता है । एक तो हमने कहा 42 के बदले कितना देते हैं, अब दूसरी बात देखिए कि केंद्र प्रायोजित योजना होती है । केंद्र प्रयोजित योजनाएं तीन तरह की मुख्यतया होती हैं । केंद्रीय योजनाएं वे होती हैं जिसमें शत-प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देती है । राज्य की योजनाएं वे होती हैं जो राज्य के अपने संसाधन से योजना चलती है और एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है। अब उस योजना के बारे में या उस योजना को संपूर्णता में देखिएगा तब आपको एहसास होगा कि राज्यों के साथ कितना बड़ा छलावा होता है । योजना वे बनाते हैं, नाम वे देते हैं, उसके शेयरिंग पैटर्न मतलब राज्य का और केंद्र का कितना लगेगा वे तय करते हैं और जो तय करते हैं वह भी समय पर नहीं देते हैं । मतलब वे 50 रुपया आपको दे दिए अब आप अपना 50 रुपया भी उनकी योजना में डालिए तब आप उनकी योजना के नाम से बिहार में काम कर सकते हैं । मतलब पैसा आपका भी गया लेकिन नाम होगा जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है । महोदय, विडंबना यह है कि लगातार सरकारिया कमीशन से लेकर सब तक, ये अभी सबसे अद्यतन ढंग से जो इनका गठन किया हुआ निकाय है, बॉडी है नीति आयोग । महोदय, खासतौर से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए ही नीति आयोग ने मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया था । उसमें बी0जे0पी0 के मुख्यमंत्री ही संयोजक थे और उन्होंने जो अध्ययन करके रिपोर्ट दिया है उसमें दिया है कि, और शुरू से ही यह बात मानी जाती रही है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या सीमित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बल्कि उसमें एक संकेत भी है कि इसकी संख्या कभी भी 30-35 से अधिक नहीं होनी चाहिए

लेकिन स्थिति क्या है ? 100 से ऊपर योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं महोदय चल रही हैं । हमको तो आश्चर्य लगता है कि जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं एक इनके भाजपा के, पता नहीं वे केंद्र प्रायोजित योजना समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं । वो केंद्र सरकार कितना मदद कर रही है, इसके बारे में 105 योजनाओं की सूची एक दिन हमने देखा कि वे सूची लहरा-लहरा कर क्लेम कर रहे हैं कि केंद्र इतनी योजनाओं में मदद करता है । महोदय, योजना उनकी होती है, हमने निर्मला जी से कहा कि भाई आपके नीति आयोग ने जो अनुशंसा की, आप ही के मुख्यमंत्रियों ने अनुशंसा की और केंद्र सरकार ने उसको मान भी लिया है, आप उसको क्यों नहीं लागू करते हैं ? जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं इसमें क्यों लगातार वृद्धि होती जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, इसमें जितनी वृद्धि होती है राज्यों पर उतना वित्तीय दबाव बढ़ता है और कारण इसका सीधा है जैसा कि हमने कहा । पैसा लगाकर भी सारा श्रेय लेने के लिए तो वे हमेशा आगे रहते हैं । ये जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार है, श्रेय और क्रेडिट हड़पने में इसका कोई जोड़ा नहीं है । कोशिश तो बिहार पर अनेक माने में किया जाता है लेकिन वह तो हमलोगों के मुख्यमंत्रीजी खुद कुशाग्र बुद्धि के हैं कि उनके जाल को काटकर निकल जाते हैं, नहीं तो उनका जाल यहां भी फेंका जाता है । कई योजनाओं का महोदय, यहां पिछले दो-तीन वर्षों से जो योजनाएं चलती रहती हैं उसमें हमारी उपलब्धि दिखने लगती है, अचानक सुनियेगा कि केंद्र सरकार ने उसी प्रकार की एक योजना की शुरूआत कर दी और कुछ पैसे उस योजना में भेज देती है जो इस योजना को इसमें मतलब subdued करती है, इसके अंदर डाल देती है । मतलब क्या है, वह कुछ पैसे डालकर जो राज्य सरकार पिछले तीन वर्षों में लगातार अपना संसाधन लेकर जो उपलब्धि हासिल की है वे उसको भी हड़प लेना चाहते हैं, निगल लेना चाहते हैं । यह कैसे होगा ? यह तो हो नहीं सकता है, कोशिश लेकिन वे महोदय बराबर करते हैं । हमने तीन बातें कहीं, एक कि वे देते नहीं हैं, दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना और तीसरा महोदय असली पेंच जो चलता है वह होता है जो पैसे केंद्रीय कर के विभाज्य होते हैं, डिविजिबल होते हैं ।

..क्रमशः..

टर्न-19/हेमन्त/03.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री(क्रमशः) : जो केंद्र के कर के पैसे आते हैं, वह दो श्रेणी के रहते हैं, दो कैटेगरी में रहते हैं । एक डिविजिबल पूल होता है, जो वह राज्यों को भी देते हैं और जो नॉन डिविजिबल पूल रहता है जो बंटता नहीं है । जैसे कोई टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी होती है, तो यह सब डिविजिबल पूल में आता है ।

लेकिन जो सेस लगाती है केंद्र सरकार या सरचार्ज लगाती है । तो वह डिविजिबल पुल में नहीं आता है । मतलब वह राज्यों से शेयर उनको नहीं करना पड़ता है । महोदय, असली कलाकारी यही होती है, असली चालबाजी यही होती है । अब इनके समय का जरा वित्तीय इतिहास उल्टा कर देख लीजिए । लगातार टैक्स वही का वही है, सरचार्ज और सेस बढ़ते जा रहा है । मतलब लोगों से पैसा भी ज्यादा वसूला जा रहा है और वह ऐसा पैसा है कि पूरे देश में हर जगह के लोगों को देना पड़ता है । वसूल रहे हैं, लेकिन वसूल कर जो बांटने की परंपरा है, वह कानूनी पेंचीदगी में उलझाकर टैक्स नहीं बढ़ाकर उस पर सेस और सरचार्ज बढ़ा देते हैं । मतलब वह राज्यों को उधर देखना भी नहीं है । महोदय, हमने उनको कहा निर्मला सीतारमण जी को कि वित्तमंत्री जी आप संविधान देखिये कि प्रावधान क्या कहता है कि सेस और सरचार्ज सिर्फ लिमिटेड पर्पज के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए लगाया जाता है । सीमित उद्देश्य होना चाहिए, सीमित समय होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि यहां पर सेस और सरचार्ज जो पिछले 20-40 वर्षों से चल रहे हैं । हमने पूछा था वित्तमंत्री जी से कि यह क्या स्थिति है ? अगर कोई सेस या सरचार्ज स्थाई प्रकृति का होते चला जा रहा है, तब आप उसको टैक्स में मर्ज कर दीजिए । टैक्स में मर्ज कर दीजिए, क्योंकि सेस और सरचार्ज तो संविधान कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए होगा और यह किसी खास उद्देश्य से होगा । लेकिन आप समझिये कि वह एक तरह से स्थाई चीज बन गयी है और केंद्र सरकार के हाथ में राज्यों के हकमारी का समझिये कि वह एक औजार हो गया है । महोदय, आप पेट्रोल के बारे में सुनियेगा, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अब जैसे पेट्रोल में अब देखिये क्या कलाकारी होती है । सब जानते हैं कि कोरोना के पहले भी और कोरोना के बाद भी जो कच्चा तेल का दाम होता है, जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, महोदय, इसके प्राईज में जबरदस्त गिरावट आयी है । बहुत गिरावट आयी, लेकिन आपने देखा होगा कि इस देश की जनता को उसका सीधा लाभ लेने से वंचित कर दिया गया । कारण था कि जो इम्पोर्ट करने का खर्च था वह तो घटा लेकिन उस पर एक्साईज ड्यूटी की भी ड्यूटी किस तरह से बढ़ाई गई, आपको उसका उदाहरण देना चाहते हैं । एक तो जनता को फायदा नहीं हो रहा है, दाम अंतर्राष्ट्रीय घट गये, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका दाम क्रैश कर गया । लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं दिया गया । अब पेट्रोल पर समझिये कि लगभग पर लीटर 20 रुपया वह सेंट्रल एक्साईज ड्यूटी लेते हैं । अब उस एक्साईज ड्यूटी में कलाकारी देखिये सिर्फ 20 रुपये में बेसिक एक्साईज ड्यूटी जो है, बेसिक एक्साईज ड्यूटी मतलब

वह डिविजिबल पूल में रहता है । अगर बेसिक एक्साईज ड्यूटी उसमें जो पैसे आयेंगे, उसमें जो राशि जमा होगी उसको राज्यों से भी उनको शेयर करना पड़ेगा, तो वसूलते हैं 20 रुपये पर लीटर, लेकिन उसमें बेसिक एक्साईज ड्यूटी वह सिर्फ 1.40 रुपया रखा है, सिर्फ 1.40 रुपया । अब बाकी लगा दिया स्पेशल एडिशनल, जरा शब्दावली दखिये । स्पेशल एडिशनल एक्साईज ड्यूटी और वह लेते हैं 11 रुपये प्रति लीटर, 11 रुपया वह लेते हैं और इसलिए नाम यह डाल दिया कि अब यह डिविजिबल पूल में नहीं जायेगा । मतलब यह उनकी मर्जी से खर्च होगा । दूसरा कर दिया कि एडिशनल एक्साईज ड्यूटी रोड और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया । सेस लगा दिया 5 रुपये, जो अभी पेट्रोल आप खरीदते हैं उसमें जो 20 रुपये सेंट्रल एक्साईज खरीदती है भारत सरकार, हम उसका ब्रेकअप बता रहे हैं, उसमें क्या-क्या घटक रहते हैं । उसमें 5 रुपये रोड और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस है । इसी तरह से एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट सेस है, वह है 2.50 रुपया । मतलब वसूले 20 और बांटने के भी रखा 1.50 रुपये से भी कम और यह इस कैटेगिरी, इस श्रेणी में पैसे डाल देने का क्या मतलब हुआ । सीधा इसका मतलब यह हुआ कि ये पैसे अब वह अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, अपनी सुविधानुसार, अपनी पसंद, अपनी नापसंद के हिसाब से लोगों को देंगे मतलब उसको बांटने की बाध्यता उनकी नहीं रहेगी । अब इसको चालबाजी समझिये महोदय । अब इस सब तरह की चालबाजी से बात होती है और तब भाजपा नेतागण ऐसा करते हैं, कहते हैं कि जैसे बिहार कोई भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर खड़ा हो गया । हम तो बता दिये कि बिहार के लोग कितने खुददार होते हैं कि बिहार के लोग किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते हैं । महोदय, ये बिहारी अस्मिता और बिहारी खुददारी होती है और महोदय, जो इन्होंने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अब, हम सरकार की उपलब्धियों की भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं । इसलिए कि हमने सदन के सामने बजट प्रस्ताव रखे हैं । हम चाहते हैं कि सब लोग सब कुछ जानें । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा की चर्चा कर रहे थे । महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने समाधान यात्रा में कुछ जगहों पर मुझे भी उसमें सहयात्री के रूप में शामिल होने का मौका दिया था । मैंने उसको नजदीक से देखा है और कई मायने में समाधान यात्रा अपने मकसद को पाने में इतनी जबरदस्त ढंग से सफल रही है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है महोदय । मुख्य रूप से जो उस प्रोग्राम का फॉर्मेटिंग था, महोदय, उसके चार अभियोग थे । चार चीजें मुख्य रूप से होती थी, क्योंकि कुछ जगह मैं साथ था । सबसे पहले तो जो योजनाएं हैं, जब धरातल पर उनका कार्यान्वयन हो रहा है, तो किस रूप में हो रहा

है । उसमें जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, उनका फीडबैक क्या है, यह जाना जाता था । स्थल पर जाकर, खेतों में जाकर, पैलारो में जाकर, सीधे जो अनुभव करना कहते हैं वह किया जाता था । दूसरा, जनसंवाद का कार्यक्रम था, जो वहां के लोग हों, खासतौर से गरीब लोगों से, दलित, महादलित, पिछड़े लोगों का, गरीब लोगों का चाहे किसी जाति के हों, गरीब लोगों का जो टोला गांव होता था, महोदय, उसमें घंटों पैदल चलकर एक-एक आदमी से बात करके उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन लेना, यह उसका दूसरा अभियोग था । इससे सीधा संबंध और सीधा संवाद क्या हो सकता है महोदय । इसी तरीके से इसका तीसरा था महोदय, कि जीविका दीदियों से संवाद और जीविका दीदी अभियान जो है, जीविका अभियान, वह क्या है, वह तो मुख्यमंत्री जी कहते ही हैं । हम भी उसके बारे में कुछ बतायेंगे ।

(क्रमशः)

टर्न-20/धिरेन्द्र/03.03.2023

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : लेकिन पहले समाधान यात्रा का समाधान हो जाय कि तीसरे अवयव में जीविका दीदियों से बात होती थी । चौथे में, जितने हमारे बहुत सारे यहाँ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, सभी सदस्यों के साथ बैठ कर जिले में जो विकास की योजनाएँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसकी समीक्षा करते थे । सभी से पूछा जाता था कि आप अपने इलाके की समस्या बताइये, जो दिक्कते हैं, दुश्वारियाँ हैं, वे बताइये और यथासंभव उनका वहीं तुरंत निदान करने का निदेश भी दिया जाता था, तो ये चार अवयव के साथ समाधान यात्रा और महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को न सिर्फ बधाई देता हूँ बल्कि बिहार की जनता की तरफ से भी इनको साधुवाद देता हूँ । महोदय, कैसे समय में यात्रा हुई थी जरा याद कर लीजिये, हाड़ कंपाने वाली ठंड थी, शीतलहर चल रही थी और उसमें, जब यात्रा में हमलोग जा रहे थे तो शीतलहर में लोगों का जो उत्साह हम देख रहे थे, खासतौर से गरीब लोग जिस ललक से, जिस लालसा में, जिस आशा और भरोसे के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलने को बेताब रहते थे और मुख्यमंत्री जी भी जिस ढंग से उनसे मिलने के लिए एकदम हमेशा आगे बढ़कर मिलते थे, यह अद्भूत था महोदय, और एक तरह से ठंड और शीतलहरी और चार-पाँच डिग्री के टेंपरेचर से, इनके समाधान यात्रा में समझिये कि कॉम्पिटिशन हो गया । उधर ठंड बढ़ते जा रही थी, इधर यात्रा और तेजी से होते जा रही थी लेकिन महोदय, आपको बताते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि अंत में ठंड हार गया, वह चला गया लेकिन समाधान यात्रा जारी

रही तो ये समाधान यात्रा थी और महोदय, समाधान यात्रा का एक चीज जो मुझे, इसका सबसे अधिक जो बाई-प्रोडक्ट बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो इसको रखा था बिहार के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए और लोगों से मिलकर, जनप्रतिनिधियों से मिलकर और जो योजनाएँ हैं उसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या आगे किया जा सकता है लेकिन अनजाने में इसका राजनीतिक निहितार्थ या राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक असर भी गजब का हो गया और वह ऐसा हो गया, याद होगा कि बहुत सारे लोग, अब तो हैं ही नहीं, क्या-क्या कहते थे कि मुख्यमंत्री जी थक गए हैं, मुख्यमंत्री अब छोड़ रहे हैं, किसी ने कह दिया कि समाधान यात्रा नहीं विदाई यात्रा है, अभी वे रहते तो हम उनको कहते कि चलिये आपको एक दिन हम दिखाते हैं, वीडियो सब जरूर हमारे जनसंपर्क विभाग में कहीं-न-कहीं बना होगा और जिस ढंग से लोग परेशान हो रहे थे कि मुख्यमंत्री जी थक रहे हैं, हमको लगता है कि समाधान यात्रा का सबसे प्रभावी बाई-प्रोडक्ट, इसको कहिये कि जो पार्श्व नतीजा निकलता है, साईड से दूसरा नतीजा जो निकला, जिन लोगों को राजनीतिक भ्रम या संशय था कि मुख्यमंत्री जी थक रहे हैं, उनके भी संशय का समाधान हो गया समाधान यात्रा में, जो उनको समझ में आ गया । महोदय, हम तो साथ रहकर, सच पूछिये तो अचरज में रहते थे कि इस उम्र में इतनी लंबी, समझिये कि प्रशासन का बोझ उठाते हुए भी जो ऊर्जा का संचार हमने देखा तो इन लोगों के द्वारा जो बार-बार कहा जा रहा है मुझे बरबस, महोदय, हमलोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी, मुझे वह कविता याद आ गयी, जब हम मुख्यमंत्री जी को बराबर जिस ललक से बढ़ते देखते थे तो हमको उसी समय से ध्यान में यह कविता घूमते रहती है, आज संयोग से आपने मौका दे दिया तो हम सोच रहे हैं कि सदन से भी साझा कर लें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है । महोदय, कविता तो 100 साल पुरानी है, संयोग देखिये कि कितना सुखद संयोग है कि कविता वर्ष 1922 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, वर्ष 1923 में प्रकाशित हुई और आज हमलोग वर्ष 2023 में हैं और महोदय, यह कविता इतनी लोकप्रिय हुई थी, इतनी इसको प्रसिद्धि मिली कि पूरी दुनिया में इस कविता का मर्म जो कहते हैं वह छा गया और महोदय, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे, वे कहिये तो अमेरिका के दिनकर थे, उन्होंने खासकर मनुष्य को कर्तव्य पथ पर चलने की जो प्रेरणादायी कविताएँ लिखी, वे हमेशा से मशहूर हैं, महोदय, 1960 के दशक में जॉन कैनेडी जब वहाँ के राष्ट्रपति बने थे और उनका इनॉगुरेशन सेरेमनी जो करते हैं, शुरूआत हो रहा था राष्ट्रपति बनने के बाद, उसमें विशेष रूप से उनको बुलाया गया ये कविता पढ़ने के लिए । कविता तो लंबी है लेकिन इसका जो मर्म है, ये

हर व्यक्ति को, हर कर्मयोगी को अपने कर्तव्य पथ पर बिना रूके, बिना थके, बिना झांके लगातार आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है, महोदय, इसके लिए ये कालजयी होगा और इसकी खासियत यही है कि जवाहरलाल नेहरू जब, वे विद्वान तो थे ही, वे जब डेथ बेड पर थे, जब वे जा रहे थे तो उनके बेड के किनारे जो किताब रखी थी कविता संग्रह, उसमें यही कविता वे बार-बार पढ़ते थे और जो चार लाईन हम बताने वाले हैं, वही चार लाईन वे अंडरलाईन कर के रखते थे और अंतिम समय में, लगता है जैसा लोगों का मानना है कि वे रोज उसको एक बार पढ़ते थे और महोदय उसकी पंक्तियाँ हैं, अभी भी उसी की पंक्ति लेकर अभी जो जॉ बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंड हैं, उन्होंने अपना मेमोराइज लिखा प्रोमिसेज में। महोदय, उसी की पंक्तियाँ हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की:

"The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

मतलब, अभी जिंदगी में इतने काम करने हैं कि बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और यह कविता इतनी कालजयी हुई है कि हर क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कितनी बार उद्धृत हुई है, हमको तो लगता है विश्व में सबसे अधिक बार उद्धृत होने वाली किसी कविता की पंक्तियों में ये है और इसकी लोकप्रियता की मिसाल देखिये कि 1960 के दशक में, कविता लिखी गई थी वर्ष 1922-23 में और 1960 के दशक में डॉ॰ हरिवंश राय बच्चन, सब ने नाम सुना होगा, उनकी एक-से-एक कृतियाँ हैं, कितने मशहूर कवि थे, उन्होंने उस कविता की चार पंक्तियों का हिन्दी अनुवाद किया था और महोदय, हिन्दी अनुवाद उसका और रोचक है, जब उन्होंने लिखा उसका हिन्दी अनुवाद करते हुए कि:

गहन-सघन मनमोहक वन तरु, मुझको आज बुलाते हैं,
किन्तु किए जो वादे मैंने, मुझे याद आ जाते हैं,
अभी कहाँ आराम बदा, इनकी बातें छलना है,
अभी तो इनको मीलों, मीलों इनको चलना है ।

महोदय, ये डॉ॰ हरिवंश राय बच्चन जी का अनुवाद है, उस कविता का। महोदय, अब कुछ योजनाओं की चर्चा कर दूँ जो बिहार की योजनाएँ, देश को छोड़िये पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है अभी जीविका की बात चल रही थी, हमलोग जहाँ-जहाँ गए, वैसे तो सब जगह जीविका दीदियों से संवाद हुआ...

...क्रमशः...

टर्न–21/संगीता/03.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : लेकिन दो–तीन उसमें से मैं जरूर उद्धृत करना चाहता हूं, एक अमोला देवी, बोधगया हमारे कृषि मंत्री जी होंगे उन्हीं के क्षेत्र जिंदापुर की थी हमको याद है, उनके पति चेनारिक मांझी जी शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, पूरा परिवार शराब के व्यवसाय में लिप्त रहता था, वह परिवार और वह टोला लेकिन पति की मृत्यु के बाद बदहाली की हालत में वह जीविका समूह से जुड़ी और फिर वह लगातार इतना आगे बढ़ी, छोटे–छोटे ऋण लेकर, 5 हजार से शुरू करके 20 हजार से शुरू करके अपने तीनों बच्चे–बच्चियों को, सबसे छोटी बच्ची को भी ग्रैजुएट करा दिया, बड़ा बेटा बिजनस करता है, जो खुद बदहाली में थी उस अमोला देवी के जीविका समूह से जुड़ने पर वह समझिए कि आज उसने खुद बताया कि हम सवा लाख रुपया महीना कमाते हैं, यह सोचिए। दूसरा हमने देखा यहां खगड़िया में, खगड़िया में एक सलिता देवी थी, महिला होकर जीविका समूह से जुड़कर उन्होंने जीविका महिला उत्पादन समूह बनाया और जीविका महिला कृषि उत्पादन समूह जो बनाया तो वह इतना सफल हुआ महोदय कि उसको समझिए कि मसूरी, देहरादून जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हमारे सिविल सर्विसेज के लोगों को, आई0ए0एस0 लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनके ओरिएंटेशन के लिए मतलब उनके उन्मुखीकरण के लिए, पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण के लिए सलिता देवी को खगड़िया से मसूरी बुलाया गया और उससे उनका प्रशिक्षण करवाया गया, ये समझिए जीविका समूह की सफलता का है और आज ही अखबार में हमने पढ़ा है महोदय आज ही के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि मुजफ्फरपुर, सकरा की बबीता देवी, वह जीविका समूह से जुड़कर जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, उनको जमा करके उससे आकर्षक खिलौने और सजावट के सामान बनाने का उसने ऐसा कारनामा किया है कि कल ही महोदय, उसको बुलाया गया है कल ही 4 मार्च को जीविका की उस दीदी को राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देने वाली हैं। महोदय, आने वाला समय बतायेगा, आने वाला इतिहास लिखेगा कि ये कितनी बड़ी मूक क्रांति हो रही है महोदय । ये समाज के अंदर में भूचाल पैदा कर रहा है, जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थीं, हम तो मुख्यमंत्री जी को बराबर कहते थे कि उनके आत्मविश्वास के साथ जब वे बोलती थीं महोदय, हमलोग फीके पड़ जाते थे उसके आत्मविश्वास और उसके बोलने के सामने, लगता था ये हमसे अच्छा बहुत अच्छा कर सकती है, अगर नेता सब बन जाय महोदय, वह तो

समझिए संजोग है कि विधान सभा में आरक्षण हमलोगों के वश में नहीं है नहीं तो. ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिए आप ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, दूसरी बात मैं बिजली की कहना चाहता हूं । हमारे अग्रज आदरणीय बिजेन्द्र बाबू बैठे हैं यहां बिजली मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के निदेशन में जो बिजली की उपलब्धि है महोदय, वह अब पृथ्वी और आकाश से देखने की चीज नहीं रही । महोदय, वह अब अंतरिक्ष से दिखता है, स्पेस से दिखता है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है और अभी ही कुछ दिन पहले महोदय, पहले चार संस्था है एक तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बैंगलोर में बेस्ड है हेडक्वार्टर, दूसरा एन0आर0एस0सी0 है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वह हैदराबाद में है, तीसरा नासा है नेशनल एयरोनेटिक स्पेश एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका वाशिंगटन में है और चौथा महोदय, एन0ओ0ए0ए0 है जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी अमेरिका में है वाशिंगटन में है । इन चारों ने मिलकर डेटा कलेक्ट तो हमारा एन0आर0एस0सी0 और इसरो के लोग करते हैं लेकिन ये फिर अपने डेटा या अपने जो विजुअल्स आते हैं स्पेस से, जो हमारे सेंट्रलाइज्ड स्पेस में घूम रहे हैं, स्पेस से अंतरिक्ष से जो पृथ्वी दिखता है उसमें बिहार में बिजली में कितनी जगमगाहट बढ़ी है इसके लिए महोदय, एक नाईट टाइम एटलस जारी करती है ये चारों मिलकर के और अभी जो उसने डिकैडल चेंज का एक नाईट टाइम एटलस निकाला है अभी वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक का तो इसके बीच में जो चेंज आया है महोदय, भारत का औसत जो इसमें प्रगति है वह है कितना 43 या 47 प्रतिशत है और बिहार में जो परिवर्तन आया है जो इसमें बढ़ोतरी हुई है रोशनी में वह 474 प्रतिशत है पूरी दुनिया में सबसे अधिक है और महोदय ये सब डेटा आंकड़े कोई हमारे तो हैं नहीं, बैंगलोर, हैदराबाद, वाशिंगटन सबने मिलकर दिया है और महोदय याद होगा कि वर्ष 2012 में ही मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से 15 अगस्त को घोषणा की थी कि अगर बिहारवासियों को बिजली में कोई सुधार नजर नहीं आएगा तो हम वोट मांगने भी नहीं आयेंगे लेकिन ये सुधार क्या ये तो करामात हो गया कि आज पूरी दुनिया अंतरिक्ष से बिहार में हुए परिवर्तन को देख रही है, सराह रही है, सबक ले रही है ये तो हमारी उपलब्धि है महोदय । इसी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है जलवायु परिवर्तन में, अभी कुछ दिन पहले महोदय यू0एन0ए0 की जो बडी है यूनाइटेड नेशंस इनवॉयरमेंट प्रोग्राम उसके कंट्री हेड आए थे, यहां जो यू0एन0ई0पी0

का बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एकरारनामा एक पैक्ट हुआ है, उसको देखकर कंट्री हेड ने कहा कि बिहार का मॉडल जो है इस मायने में जो क्लाइमेट रेजिलियेंस कहते हैं, क्लाइमेट रेजिलियेंस में मतलब इसको फिर से संजोने का, जो जलवायु है इसको पर्यावरण को संरक्षण और सुरक्षित करने का, इसमें जो बिहार मॉडल है इसको ग्लोबली एडॉप्ट किया जाना चाहिए, मतलब दुनिया भर को बिहार मॉडल की नकल करनी चाहिए यह यू0एन0ई0पी0 के कंट्री हेड बोलते हैं । महोदय, इससे ज्यादा हमको क्या प्रमाण पत्र चाहिए तो भाई इनका पता नहीं इनलोगों के सीने में कैसा दिल बसता है कि बिहार की जब पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है तब भी इनका कोई मन हिलता-डुलता नहीं है, अंध आका भक्ति में, क्या-क्या बोल जाते हैं, बिहारियों का बिहार की धरती का अपमान करने से नहीं चूकते । इसलिए महोदय, हमने जो बजट प्रावधानों को दिया है हम आज अपनी बात कहते हैं और हम अपनी बात समाप्त करने से पहले यही अनुरोध करेंगे कि अब इसमें जो मदवार लिया जायेगा और मतदान के लिए रखा जाएगा उसमें सदन उसको सर्वसम्मति से पारित करे क्योंकि हमारी उपलब्धियां भी ऐसी हैं महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-03 मार्च, 2023 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-49 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

आज की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व सदन में विपक्ष के द्वारा जिस तरह से आचरण किये जा रहे हैं, उसके संबंध में मैं सदन को कुछ बतलाना चाहता हूं । माननीय सदस्यगण, इस अष्टम सत्र के दूसरे दिन से ही यह देखा जा रहा है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों का आचरण सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं हो रहा है । इस आसन से माननीय सदस्यों को सदैव ही मर्यादित आचरण करने हेतु अनुरोध किया जाता है, लेकिन वे आसन का भी सम्मान नहीं करते । आसन की तरफ ऊंगली दिखाते हैं, बिना इजाजत के खड़े होकर ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं, मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वेल में आकर कुर्सियां उठायी जाती हैं, टेबल पीटे जाते हैं, जिससे विधान सभा के पदाधिकारियों को, जो वहां पर बैठकर कार्य करते हैं, उन्हें भारी कठिनाई होती है । विरोधी दल के माननीय सदस्यों का इस प्रकार का आचरण सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है । ये सारे

प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर वे सरकार से नहीं सुनते हैं बल्कि सदन में अशोभनीय आचरण कर प्रश्नकाल में सदा अवरोध पैदा करते हैं यह बहुत ही दुखद है । आज तो हद ही हो गयी, माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार, श्री जनक सिंह, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री लखेन्द्र कुमार रौशन ने जिस तरीके से आज सदन में आचरण और व्यवहार किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि संसदीय लोकतंत्र और संसदीय परंपरा में उन्हें कोई आस्था नहीं है, यह निंदनीय है ।

माननीय सदस्यगण, सरकार भी बैठी हुई है, मैंने अपनी भावना को आसन से इसलिये व्यक्त किया कि यही स्थिति बनी रही और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार करने में नित दिन ये जुटे रहेंगे, तब मजबूर होकर इस तरह के अशोभनीय, असंसदीय आचरण करने वाले जो माननीय सदस्य होंगे विरोधी पक्ष के, मैं बाध्य हो जाऊंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श लेकर के वैसे सदस्यों को शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले, उन्हें सदन से निष्कासित करने का भी मैं निर्णय लूंगा ।

अंत में, अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक- 06 मार्च, 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।